

क्रान्ति सामय

क्रान्ति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रसारित

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार, 02 मई 2022 वर्ष-5, अंक-96 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com f www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दिल्लीवालों को मई में और सताएगी भीषण गर्मी, सामान्य से ज्यादा रहेगा तापमान

नई दिल्ली। दिल्ली के लोगों को मई महीने में भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार को अनुमान जताया कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान में अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। यानी रात में भी गर्म हवाओं का प्रकोप रह सकता है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. एम मोहापात्रा ने शनिवार को मई में गर्मी और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी राज्यों, पश्चिम मध्य तथा उत्तर-पूर्व भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई में पारा सामान्य से अधिक जबकि शेष में सामान्य से कम रहने की संभावना है। वहीं, देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार हैं। मोहापात्रा ने कहा कि अप्रैल में गर्म हवाओं के कारण देश के मध्य व उत्तर पश्चिमी हिस्सों में दर्ज तापमान पिछले 122 सालों में सबसे अधिक रहा। उत्तर पश्चिम हिस्से में औसत अधिकतम तापमान 35.90 और मध्य में 37.78 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग के मुताबिक, मार्च और अप्रैल में मध्य हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहा। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक रहा। इससे पहले मार्च 2022 देश के साथ-साथ उत्तर पश्चिम भारत के लिए 122 वर्षों में सबसे गर्म था। विभाग के मुताबिक, मई में पूरे महीने अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार बने हुए हैं। हालांकि, बीच-बीच में धूल भरी आंधी और मामूली बौछरें तापमान एक-दो डिग्री जरूर कम करेंगी। इस बीच, शनिवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक गर्म जगह खेल परिसर रही। यहां सबसे अधिक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार देने की उठी मांग मुफ्त राशन स्कीम पर बीएसई के सीईओ ने सरकार की तारीफ की

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठने लगी है। बॉम्बे एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार देने पर विचार किया जाना चाहिए। बीएसई के सीईओ ने इसके लिए कोविड-19 के दौरान सरकार की उपलब्धियों को सराहा, साथ उन्होंने कहा कि देश में कोरोना काल में गरीबों को मिली मानवीय सहायता के लिए हमें भारतीय होने के नाते गर्व है।



आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि यह अविश्वसनीय है, जिसे हम ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी माना है। इस दौरान उन्होंने बीते साल नोबेल पुरस्कार पाने वाले संयुक्त राष्ट्र वलुंड फूड प्रोग्राम और सरकार के प्रयासों की तुलना की। बीते शुक्रवार को उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता के दीक्षांत समारोह में कहा कि कोरोना महामारी को दौरे पर 80 करोड़ लोगों को जिस फ्री राशन योजना ने फायदा पहुंचाया वह पिछले साल नोबेल पुरस्कार पाने वाली यूनाइटेड नेशन के वलुंड फूड प्रोग्राम की तरफ से किए गए कार्यों से काफी ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने इशारों में पीएम मोदी को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की। इस स्कीम ने भारत को अराजकता से बचाया बॉम्बे एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने आगे कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तौर पर पहचानी जाने वाली मुफ्त राशन स्कीम ने भारत के गरीब नागरिकों को अराजकता और दुख से बचाया है। उन्होंने कहा कि दो साल तक जितने लोगों को मुफ्त भोजन दिया गया, उनकी संख्या पूरे यूरोप या अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा या पूरे दक्षिण अमेरिकी देशों से ज्यादा थी। जो कि अपने आप में अद्भुत है।

कोयले की कमी के कारण बिजली संकट ने तोड़ा 6 साल का रिकॉर्ड, इन राज्यों का हाल बेहाल

नई दिल्ली। देश में भीषण गर्मी के बीच कोयले के संकट से बिजली संकट गहरा गया है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते छह वर्षों में पहली बार इस तरह का बिजली संकट हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार देश में अप्रैल-2022 के पहले 27 दिन में मांग की तुलना में 1.88 बिलियन यूनिट बिजली का संकट रहा है जिसने बीते छह साल के बिजली संकट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को देश में 2,07.11 मेगावॉट बिजली की मांग रही जिसने अबतक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। 26 अप्रैल को बिजली आपूर्ति की तुलना में मांग इतनी अधिक हो गई थी कि देश में 8.22 गीगावॉट बिजली का संकट हो गया था। ऊर्जा मंत्रालय की मानें तो इस वर्ष मार्च में बिजली की मांग में 8.9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही नहीं मंत्रालय का कहना है कि बिजली की मांग ऐसे ही जारी रही तो मई-जून में बिजली की मांग 21.5 से 22.0 गीगावॉट हो सकती है। इन राज्यों में बिजली कटौती सबसे अधिक कोयला संकट के कारण हरियाणा, राजस्थान,

गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों में बिजली का संकट अधिक है। मालूम हो कि पिछले साल अक्टूबर में भी इसी तरह का बिजली संकट गहराया था। हालांकि इस बार स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि देश के अधिकतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में संकट के कारण कई घंटों की कटौती की जा रही है। ओडिशा में कोयले के अभाव में एनटीपीसी का एक संयंत्र बंद है जिससे 800 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होता है। 25 फीसदी से कम कोयले का भंडार बिजली संकट पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का दावा है कि देश के 173 ऊर्जा संयंत्रों में से 106 के पास 25 फीसदी से कम कोयले का भंडार है। देश में रोजाना 22 लाख टन कोयले की जरूरत है और आपूर्ति सिर्फ 16 लाख टन हो रही है। नतीजा ये है कि हाल के सप्ताह में रोजाना औसतन 16,035 मेगावॉट बिजली की मांग हो रही है जबकि आपूर्ति सिर्फ 2304 मेगावॉट की हो रही है। यही कारण है कि मांग की तुलना में यूपी में नौ, हरियाणा में 7.7 और उत्तराखंड में 7.6 फीसदी बिजली संकट है।

लखीमपुर खीरी में फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारी ! 5 मई को जुट रहे हैं 4 राज्यों के किसान

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर किसान नेता जुटने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यूनियन 5 मई को लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर में किसानों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी। उस दौरान कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। बीकेयू का कहना है कि किसान मृतकों को इंसफ दिलाने के लिए लखीमपुर पहुंच रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भारतीय किसान यूनियन (पंजाब) के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि स्यूक के बैनर तले किसान यूनियन बीते साल मारे गए



किसानों को इंसफ सुनिश्चित करने के लिए 5 मई को लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब से किसान 4 मई को रवाना होंगे और रास्ते में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के साथ लखीमपुर खीरी जाएंगे। लखीमपुर मामले में नया क्या लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आरोपी के

खरीद में खत्म की आधार सत्यापन की अनिवार्यता दरअसल, लखीमपुर खीरी घटना के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों ने जमानत के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। घटना के बाद मिश्रा को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। बीते साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। मिश्रा ने केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ा दी थी। घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन की अगुवाई में समिति गठित की थी।

12-14 वर्ष के आयुवर्ग में 60 फीसद से अधिक लाभार्थियों को मिल चुकी पहली खुराक

नई दिल्ली। देश में घातक कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। पिछले साल जनवरी माह से शुरू कोरोना वैक्सिनेशन अभियान के तहत अब 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सिनेशन की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं देश में 60 फीसद से अधिक 12 से 14 साल के बच्चों व किशोरों को वैक्सिनेशन की पहली खुराक मिल चुकी है। यह आंकड़ा केंद्र की ओर से जारी किया गया है। 12-14 वर्ष के आयुवर्ग में 60 फीसद से अधिक लाभार्थियों को कोरोना वैक्सिनेशन की पहली खुराक दी जा चुकी है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया



ने शनिवार को दी। मंडाविया ने ट्वीट कर कहा, 12-14 आयुवर्ग में 60 फीसद से अधिक बच्चों व किशोरों को कोरोना वैक्सिनेशन की पहली खुराक मिल चुकी है। वैक्सिनेशन ले चुके सभी युवा मित्रों को बधाई। हमें आप सब पर गर्व है। चलिए इस अभियान को जारी रखते हैं। रविवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में कोरोना वैक्सिनेशन का आंकड़ा 188.89 करोड़ से अधिक हो चुका है।

होम आइसोलेशन में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा चार हजार के पार, दिल्ली में 5.10 हुई संक्रमण दर; एक की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के 1520 नए मरीज मिले। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1412 रही। जबकि कोरोना के चलते एक की मौत हो गई। वहीं होम आइसोलेशन में मरीजों का आंकड़ा चार हजार को पार कर गया। शनिवार को जारी कोविड-19 स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 29775 लोगों की जांच की गई। जिसमें आरटीपीसीआर से 20116 और रैपिड एंटीजन टेस्ट से 9659 लोगों की जांच हुई। कोरोना संक्रमण की जांच दर 5.10 फीसदी रही। कोरोना को लेकर अब तक 37854580 सैंपल की जांच हो चुकी है। होम आइसोलेशन में कोरोना के 4044 मरीजों का उपचार जारी है। जबकि



अस्पताल में कोरोना संक्रमित व सदिग्ध मरीज मिलाकर कुल 154 मरीज इलाज के लिए भर्ती हैं। आइसोचू में 48 मरीज और वेंटिलेटर पर दो मरीज भर्ती हैं। अलग-अलग अस्पतालों में 9432 बेड खाली हैं। दिल्ली में कटेनमेंट जोन की संख्या 769 हो गई। कोरोना के कुल 1883075 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें 1851184 मरीजों ने कोरोना को मात दी और कुल

संक्रमण दर 4.97 फीसदी है। साथ ही 26175 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। जबकि कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5716 हो गई है। 40 हजार से अधिक लगी वैक्सिनेशन डोज बीते 24 घंटे में 40132 वैक्सिनेशन की डोज लगाई गई। जिसमें पहली डोज लेने वाले लोगों की संख्या 5605 और दूसरी डोज वालों की संख्या 20384 रही। जबकि 14143 बीते 24 घंटे में प्रिकोशन डोज ली। वहीं अभी तक 15-17 वर्ष आयु के किशोरों को 1774653 वैक्सिनेशन की डोज और 18 या उससे अधिक वालों को 729881 को प्रिकोशन (बूस्टर) डोज लगी है।

बिजली समस्या में सुधार दिखने में लग सकते हैं दस दिन, स्थिति से निपटने में केंद्र का सारा सिस्टम हुआ सक्रिय

नई दिल्ली। देश में बिजली की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने में हफ्ते भर से लेकर दस दिन तक का समय लग सकता है। बिजली की रिकार्ड मांग से उपजी स्थिति से निपटने में केंद्र सरकार का सारा सिस्टम सक्रिय हो चुका है। तापीय बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई है तो कोयला डुलाई के लिए ज्यादा रोक भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ज्यादा कीमत की परवाह किए बिना राज्यों को बाहर से कोयला आयात करने को कहा गया है। आयात आधारित तापीय बिजली घरों में ज्यादा उत्पादन हो भी रहा है। केंद्र ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपना दायित्व

निभाते हुए कोयला कंपनियों के साथ ही बिजली कंपनियों की बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करें। इसके बावजूद हालात को संभालने में 10 दिन का समय लग सकता है। गैर भाजपा शासित राज्यों का लचर रवैया बिजली मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति को लेकर कुछ समस्याएं निश्चित तौर पर पैदा हुई हैं लेकिन हालात काबू में ही रहेंगे। दस दिन के भीतर स्थिति काफी हद तक ठीक हो जाएगी। हालांकि बिजली की काफी ज्यादा मांग को देखते हुए पूरे सिस्टम को सतर्क रहना

होगा। बिजली मंत्रालय ने राज्यों अपना सिस्टम प्लांट को कोयले की आपूर्ति भी बाधित हो रही है क्योंकि ये समय पर कोयला खरीद का आर्डर नहीं कर पा रहे। भुगतान में भी फिसट्टी गैर भाजपा शासित राज्य यही स्थिति कोयला कंपनियों के बकाये को लेकर है। कुछ समय राज्यों पर 15,600 करोड़ रुपये का बकाया था। लेकिन पिछले एक पखवाड़े में कुछ राज्यों ने भुगतान किया है लेकिन फिर भी अभी 7,918 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर 2,591.45 करोड़, बंगाल पर 955.44 करोड़, झारखंड पर 1018.22 करोड़,

तमिलनाडु पर 705 करोड़ का बकाया है। इस बकाये के कारण फिलहाल ये राज्य ज्यादा मात्रा में कोयला नहीं खरीद सकते। यही वजह है कि सरकार कह रही है कि, समस्या कोयले की नहीं है। बिजली संयंत्रों को रोजाना 22.5 लाख टन कोयला चाहिए, जबकि कोल इंडिया उन्हें रोजाना औसतन 17 लाख टन कोयला पहुंचा रहा है। बिजली संयंत्रों के पास औसतन नौ दिनों का कोयला है। स्थिति पिछले साल सितंबर-अक्टूबर से बेहतर है। मई के अंत तक और बढ़ेगी मांग सनद रहे कि 29 अप्रैल, 2022 को देश में 2.07 लाख मेगावाट बिजली की मांग रही

जो अप्रैल, 2021 के मुकाबले 17.14 फीसद ज्यादा है। पिछले 40 वर्षों में बिजली की मांग में तेज वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि मई, 2022 के मध्य या अंत तक बिजली की मांग 2.20 लाख मेगावाट तक पहुंचेगी। कोल इंडिया का कहना है कि अप्रैल, 2022 में उन्होंने 14 फीसद से ज्यादा कोयले की आपूर्ति की है। मई, 2022 में यह और ज्यादा होगी बशर्ते पर्याप्त रेलवे रोक उपलब्ध हों। बिजली मंत्रालय का कहना है कि अभी 411 रेलवे रोक उपलब्ध हैं जिनकी संख्या बढ़ कर अगले कुछ दिनों में 440 से ज्यादा हो सकती है। इससे कोयला की आपूर्ति और बढ़ जाएगी।

संपादकीय

कटौती की आहट

बुधवार को कोरोना संक्रमण में वृद्धि की चुनौती से मुकाबले के लिये राज्य के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री के संवाद के लिये बैठक बुलाई गई थी। मगर बाद में इसमें पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई का मुद्दा हावी हो गया। प्रधानमंत्री का कहना था कि विपक्षी दलों शासित राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क घटाने के बावजूद वैट में कटौती करके पेट्रोल-डीजल उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र से राजग सरकार के दौरान बढ़ाए गये उत्पाद शुल्क को घटाकर महंगाई कम करने की मांग की है। यह सर्वविदित है कि कोरोना संकट के लगभग दो वर्ष के दौरान तमाम लोगों की आय में गिरावट आई है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को आम जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार दिखाना चाहिए। समाज में कमाबेश हर वर्ग की आय में संकटचन हुआ है। हालिया आंकड़ों के अनुसार करीब चार करोड़ लोग उच्च मध्यम वर्ग से निम्न मध्यम वर्ग में आ गये। जब तक आय के नये अवसर बनें और रोजगार संकट खत्म हो सके, तब तक सरकारों को किसी न किसी तरह राहत देने की पहल करनी चाहिए। दरअसल, केंद्र सरकार ने बीते साल नवंबर में उत्पाद शुल्क को कम करके राज्य सरकारों से पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट घटाने का आग्रह किया था। भाजपा शासित राज्यों को तो इसमें अपनी सुविधा के अनुसार कमी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों वाली सरकारों मसलन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड तथा तमिलनाडु ने वैट में कमी करके उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी। जैसा कि जाहिर था कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान के बाद तीखे हमले किये। कांग्रेस ने मांग की कि पहले राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट के दौरान बढ़ाये गये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करके राहत दे। साथ ही दलील दी कि यूपीए शासन के दौरान हर साल एक लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाती रही है। जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मामलों के मंत्री सरकार के बयान में उतरे। उनकी दलील थी कि भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले दूसरे दलों की सरकारों में पेट्रोल व डीजल पर वैट की दर करीब दुगुनी है, जिसे लोगों को राहत देने के लिये कम किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि राज्यों की सरकारों को अन्य मदों से अतिरिक्त आय जुटानी चाहिए। यह कट्ट सत्य है कि देश करीब अस्सी फीसदी कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। फिर राज्यों के पेट्रोल पंपों के जरिये इसकी खुदरा बिक्री होती है। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि मूल खरीद मूल्य के मुकाबले करीब दुगुने मूल्यों पर इसकी खुदरा बिक्री होती है। दरअसल, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल दाम में उत्पाद शुल्क, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट मिलाकर इस्की अंतिम कीमत का निर्धारण होता है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाला वैट राज्य सरकारों की आय का मुख्य जरिया है। साथ ही अन्य मुख्य आय स्रोतों में शराब व संपत्ति पर लगने वाला कर है। जीएसटी से पहले आय केंद्र को होती है और फिर राज्यों को उनका हिस्सा दिया जाता है, जिसके बंटवारे व समय पर न मिलने को लेकर केंद्र व राज्यों में लगातार तनाव ही रहा है। सही मायनों में पेट्रोलियम पदार्थों की आर्थिकी को राज्य अपनी कामधेनु मानते हैं और इसमें कटौती को आसानी से तैयार नहीं होते।

आज के कार्टून



मनुष्यता

श्रीराम शर्मा आचार्य

भगवान ने मनुष्य के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, बल्कि उसे अमानत के रूप में कुछ विभूतियां दी हैं, जिनको सोचना, विचारणा, बोलना, भवनाएं, सिद्धियां-विभूतियां कहते हैं। ये सब अमानत हैं। ये मनुष्यों को इसलिए नहीं दी गई हैं कि उनके द्वारा वह सुख-सुविधाएं कमाए और स्वयं के लिए प्यारी या विलासिता के साधन इकट्ठे करे और अपना अहंकार पूरा करे। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इसलिए उसको दी गई हैं कि इन चीजों के माध्यम से वो जो भगवान का इतना बड़ा विश्व पड़ा हुआ है, उसकी दिक्कतें और कठिनाइयों का समाधान करे और उसे अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयत्न करे। इसलिए जो कुछ भी उसको विशेषता दी गई है, उसको उतना बड़ा जिम्मेदार आदमी समझा जाए और वह जिम्मेदारी उस रूप में निभाए कि सारे के सारे विश्व को सुंदर बनाने में, सुव्यवस्थित बनाने में, समुन्नत बनाने में उसका महान योगदान संभव हो। भगवान का बस एक ही उद्देश्य है-निःस्वार्थ प्रेम। इसके आधार पर भगवान ने मनुष्य को इतना ज्यादा प्यार किया। मनुष्य को उस तरह का मस्तिष्क दिया है, जितना कीमती कंप्यूटर दुनिया में आज तक नहीं बना। मनुष्य की आंखें, कान, नाक, आंख, वाणी एक से एक चीज ऐसी हैं, जिनकी रूपायों में कीमत नहीं आंकी जाती। मनुष्य के सोचने का तरीका इतना बेहतरीन है, जिसके ऊपर सारी दुनिया की दौलत न्योछावर की जा सकती है। ऐसा कीमती मनुष्य और समर्थ मनुष्य-जिस भगवान ने बनाया है, उस भगवान की जरूर आकांक्षा रही है कि मेरी इस दुनिया को समुन्नत-सुखी बनाने में यह प्राणी मेरे सहायक के रूप में, कर्मचारी के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, राजकुमार के रूप में काम करेगा और मेरी सृष्टि को समुन्नत रखेगा। मानव जीवन की विशेषताओं का और भगवान के द्वारा विशेष विभूतियां मनुष्य को देने का एक और भी उद्देश्य है। जब मनुष्य इस जिम्मेदारी को समझ ले और समझ ले, 'मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे अब क्या करना चाहिए?' यह बात समझ में आ जाए, तो समझना चाहिए कि इस आदमी का नाम मनुष्य है, और इसके भीतर मनुष्यता का उदय हुआ और इसके अंदर भगवान का उदय हो गया और भगवान की वाणी उदय हो गई, भगवान की विचारणाएं उदय हो गईं।

जी. पार्थसारथी

भारत के दो पड़ोसी देश, श्रीलंका और पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें भारी विदेशी सहायता की जरूरत है। ठीक इसी समय खुशी की बात है कि आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन गया है। वर्ष 2022 के लिए अर्थव्यवस्था में 7.5 फीसदी वृद्धि दर पाकर बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक माना जा रहा है। बांग्लादेश का वस्त्र-निर्यात देश की सकल निर्यात कमाई का 80 प्रतिशत है। हालिया सालों में उसके कुछ अन्य उद्योग जैसे कि प्राकृतिक गैस, दवा उद्योग, स्टील और खाद्य प्रसंस्करण में हुए विस्तार के कारण इन क्षेत्रों में भी विदेशी निवेश बढ़ा है। बांग्लादेश ने श्रीलंका से साथ 20 करोड़ डॉलर मूल्य का करंसी-स्वैप मंजूर किया है। बिमस्टेक संगठन का आखिरी शिखर सम्मेलन 30 मार्च को कोलंबो में हुआ था, जहां परस्पर क्षेत्रीय सहयोग बनाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं उलीकी गयी हैं, अलबत्ता परियोजनाओं के लिए संबंधित कारणों से पर्यटन से होने वाली लाभग सारी आय जाती रही। अरब की खाड़ी के मुल्कों से श्रीलंकाई कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा में भी बहुत कमी आई है। हालांकि बहुत से श्रीलंकाइयों को विश्वास है कि उनकी समस्याएं मुख्य रूप से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सहित राज करने वाले कुलीनों की गलतियों और अदूरदर्शिता का नतीजा है। वर्ष 2021 में राजपक्षे सरकार द्वारा रासायनिक खाद के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से इनमें एक नाराजगी और जुड़ गई। इस कदम से फसल उत्पादन में भारी कमी हो गई, खासकर चावल में। इससे देशभर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन और भड़क उठा, लोग सरकार पर अर्थव्यवस्था के कथित कुम्बंघन का आरोप मढ़ रहे हैं। इसी बीच यह चिंता बनी हुई है कि नकदी का बेतरह टोटा सह रहे श्रीलंका को भविष्य में चीन के प्रभाव के कारण हम्बन्तोता बंदरगाह में चीनी सैन्य

अड्डा बनाने की मंजूरी न देनी पड़ जाए। इस बंदरगाह का विकास चीनी मदद से हुआ है। भारत ने जापान के साथ मिलकर कुशलतापूर्वक उपाय किए हैं ताकि कोलंबो बंदरगाह, जहां से होकर काफी मात्रा में भारतीय माल आने जाता है, उसपर चीन का एकाधिकार या दबदबे वाला नियंत्रण न बने। हाल ही में एक 35 वर्षीय संधि में कोलंबो बंदरगाह के विस्तार कार्य में श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी को साथ रखकर भारत के अडानी ग्रुप के पास 51 फीसदी हिस्सा रहेगा। इस परियोजना के लिए धन जापान देगा। यह सुविधा चीन की मदद से चल रहे कोलंबो इंटरनेशनल कन्टेनर पोर्ट टर्मिनल के एकदम साथ सटी हुई है। कोलंबो बंदरगाह पर कुल नौवहनीय आवगमन का लगभग 75 फीसदी भारत से आने-जाने वाली वस्तुओं का है। महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका सरकार अपनी वित्तीय चुनौतियों से उबरने की खातिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से दीर्घकालीन इंतजाम के लिए वार्ता जारी रखे हुए है। भारत ने इस संस्था से श्रीलंका की मदद जल्द करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी अमेरिका यात्रा में श्रीलंका को फौरी सहायता करने के लिए भावपूर्ण आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी श्रीलंका के साथ अपनी बातचीत को 'फलदायक तकनीकी वार्ता' बताया है। कोलंबो के सूत्रों के मुताबिक, जब से भारत ने श्रीलंकाई सरकार के साथ मिलकर और वित्तीय सहायता करके इस संकट की घड़ी में सहायता का यत्न किया है इन गतिविधियों को गति मिली है। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और श्रीलंका सरकार ने संयुक्त रूप से 2 फरवरी, 2022 के दिन पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद के लिए 50 करोड़ डॉलर मूल्य के लाईन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, 10 खेपों में कुल 4 लाख टन ईंधन अभी तक श्रीलंका भेजा गया है। इसके अलावा इस साल जनवरी में भी, भारत ने श्रीलंका की वित्तीय मदद की थी, जिसके अंतर्गत 40 करोड़ डॉलर मूल्य का करंसी-स्वैप, एशियन वलीयोरिंग यूनियन के बकाए में पहले 51.5 करोड़ डॉलर और फिर 49.9 करोड़ डॉलर के भुगतान को टालना मंजूर किया। दीर्घ कालीन सहायता में, भारत ने वर्ष 2022 की पहली तिमाही में श्रीलंकाई नागरिकों की मदद हेतु 3 बिलियन डॉलर मूल्य की राहत प्रदान की है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के मुल्कों में श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते प्राकृतिक रूप से शांति और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। भारत के लिए संतोषजनक है कि पूरबी पड़ोसियों में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ हमारे संबंध मजबूत बने हुए हैं।

म्यांमार के साथ भारत की 1640 किलोमीटर लंबी किंतु विद्रोही गतिविधियों से ग्रस्त साझी सीमा रेखा है। सीमा की संवेदनशीलता और म्यांमार तक चीन की पहुंच होने के कारण भारत ने उसकी सैन्य सरकार के साथ निकट संबंध बनाए हुए हैं। यह नीति हमारे लिए लाभप्रद है क्योंकि इससे सीमा पार से अभियान चलाने वाले विद्रोहियों से निबटने में काफी मदद मिलती है। इन गुटों के सदस्य म्यांमार से होकर चीन के युन्नान प्रांत में आते-जाते हैं। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति की वजह से भारत ने सीमांत सड़कें और बंदरगाह बनाने में म्यांमार की मदद की है। ये कदम हमारी उत्तर-पूरबी सीमाओं को स्थिर एवं शांतिपूर्ण रखे हुए हैं। कोई हेरानी नहीं कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते आईएसआई द्वारा सशस्त्र अलगाववादियों को मदद जारी रखने की हरकत से जुड़े हुए हैं, खासकर जम्मू और कश्मीर में। हालांकि पिछले सालों में, कुछ वक्त ऐसा भी रहा जब पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मंसूबों को घटाया था। मौजूदा सैन्याध्यक्ष जनरल बाजवा की इस साल अक्टूबर माह में होने वाली सेवानिवृत्ति के बाद भी क्या यही नीति जारी रहेगी या नहीं, यह देखना बाकी है। इमरान खान का रिकॉर्ड सशस्त्र अलगाववादियों का मददगार रहने वाला रहा। इसी बीच नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने मुल्क की आर्थिक प्रगति को उच्चतम तरजीह देना तय किया है और हो सकता है इसके लिए वह भारत के साथ व्यापार, आर्थिक और नागरिक स्तर पर आपसी आदान-प्रदान करने के रिश्ते बनाने के खिलाफ न हों। तथापि वे खुद अगले साल अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव तक सत्ता में रहे पाते हैं या नहीं, यह वक्त बताएगा। इमरान खान जो भी चुनौतियां देने में समर्थ हैं या देंगे, उन्हें हल्के में न लें। कोविड महामारी से पेशे चुनौती का सामना करने में तमाम दक्षिण एशियाई मुल्कों को गंभीर दिक्कतें हो रही हैं। कोविड एक या अन्य रूप में अनिश्चितकाल के लिए जारी रहने वाला है। भारत अपने तमाम जरूरतमंद पड़ोसियों की मदद बेहतर ढंग से वैश्वीन की आपूर्ति और आवंटन के जरिए कर सकता है। पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान मलिक ने समझदारी दिखाते हुए कहा है कि यदि पाकिस्तान को मजबूत होना है तो अलग-थलग रहने की बजाय वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदमताल करनी होगी। उम्मीद करें कि शाहबाज शरीफ भारत के साथ रिश्ते रखने में इस नेक सलाह पर अमल करेंगे।

लेखक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं।

स्कूलों की उस दुत्कार ने उनकी जिंदगी बदल डाली

भूमिका श्रेष्ठ, नेपाली समाजसेवी

कोई भी वर्जना जब टूटती है, तब इंसायनित मुस्कराती है। इनको तोड़ने के लिए किन्ती गहरी प्रतिबद्धता चाहिए, यह राजा राममोहन राय, मोहनदास करमचंद गांधी जैसे महानायकों में कोई बहुत आसानी से देख सकता है। मगर इस दुनिया में ऐसे अनेक गुमाननायक-नायिका हुए; होते रहे हैं, जो अपने प्रयासों से इस धरती को कुछ और सुंदर, कुछ और करुणा, कुछ और मानवीय बनाकर विदा हो जाते हैं। कनाडा के तरक्रीपसंद प्रधानमंत्री जस्टिन टूडेव शुक्रवार को जब अपने देश में समलैंगिक समुदाय के रक्तदान पर लगी रोक हटा रहे थे, तब अनायास ही नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ का अक्स जेहन में उभर आया। थर्ड जेंडर के लिए भूमिका के संघर्ष को देखते हुए अमेरिका ने उन्हें दुनिया की साहसी महिलाओं में गिना है। जनवरी 1988 में काठमांडू के एक आम मध्यवर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता कुमार श्रेष्ठ और मां नुमाया बहुत खुश थे कि उनके घर बेटे की आमद हुई है। रुढ़िवादी समाज ने उन्हें यह गर्व थमाया था। शिशु का नाम कैलाश रखा गया। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, कैलाश के हाव-भाव लड़कियों के ज्यादा करीब पाए गए। उलझन बढ़ती जा रही थी। जो नहीं हैं, उसका किरदार तो कुछ पलों के लिए कोई भी कुशल कलाकार निभा जाए, मगर दिन-रात उसको जीना बेहद मुश्किल था। कोई कैलाश की मनस्थिति समझ नहीं रहा था। सब उसे बस यही सात्वना देते कि ये वक्ती बदलाव हैं, बड़े होने पर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन न ऐसा होना था, न हुआ। कैलाश लड़कें की पहचान के साथ असहज ही रहे। हर मध्यवर्गीय नेपाली अभिभावक की तरह उनके माता-पिता भी यही चाहते थे कि कैलाश एक लायक बेटे की तरह विदेश जाएं और परिवार के लिए धन कमाएं। लेकिन कैलाश के लिए एक अस्वाभाविक जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा था। फर्बितो, दुर्ल्यवहारों और उपेक्षाओं से किशोर मन बुरी तरह आहत हो उठा था। स्कूल में भी शिकायतें बढ़ने लगी थीं और आखिरकार एक दिन प्रिंसिपल

ने साफ-साफ कह दिया कि वह लड़कियों के साथ नहीं खेलें। लेकिन कैलाश तो उनके बीच ही सहज थे, चाहेकर भी खुद को बदलना उनके लिए मुश्किल था। नतीजतन, नौवीं कक्षा में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। कहा गया, स्कूल में 'थर्ड जेंडर' के दाखिले की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसकी सोहबत में बच्चे गिगड़ेंगे। जिस समाज में मा-बाप ऐसी संततियों की पहचान छिपाने के सारे जतन करते हों, यहां तक कि उन्हें त्याग देते हों, वहां कैलाश की मां ने हमेशा उनका साथ दिया। वह उनको लेकर कई स्कूलों में गईं, ताकि कैलाश की तालीम मुकम्मल हो सके। उनकी संतान के पास कोई तो डिग्री हो, जिससे उसकी जिंदगी शायद कुछ आसान हो जाए। मगर हर जगह निराशा मिली। कोई भी विद्यालय थर्ड जेंडर को दाखिले देने को तैयार नहीं था। नतीजतन, नौवीं कक्षा में ही पढ़ाई छूट गई, लेकिन मां ने साथ नहीं छोड़ा। स्कूलों से मिली इस दुत्कार ने कैलाश की पूरी भूमिका बदल दी। उन पीड़ादायक पलों में उन्होंने यही सोचा कि आखिर उनके जैसे लोग भी तो इंसाज ही हैं, अन्य नेपाली नागरिकों को मिले अधिकारों से उन्हें क्यों वंचित किया गया है? वे क्यों नहीं पढ़ सकते? उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? उनके नाम से जमीन की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती? औरों की तरह उन्हें भी गरिमायुी जिंदगी जीने का हक है। इस सवालों ने कैलाश को डेहलित कर दिया था, वह लैंगिक अल्पसंख्यकों के संगठन 'ब्लू डायमंड सोसायटी' से जुड़ गए। कैलाश ने अपनी वास्तविक पहचान की जंग लड़नी शुरू की। कैलाश दमन हो चुका था, अब भूमिका की भूमिका जीवंत हो चुकी थी। सत्ता और समाज को इस तीसरे वर्ग के प्रति संवेदनशील बनाने का काम आसान नहीं था। लोग उन्हें हेय नजरों से देखते थे। 'ब्लू डायमंड सोसायटी' के बैनर तले अगर किसी संगोष्ठी में लोगों को बुलाया जाता, तो लोग कतराकर निकल जाते कि कहीं वे भी

ट्रांसजेंडर न बन जाएं। लेकिन भूमिका और उनके साथियों को तो दुत्कारों और तिरस्कारों से ही लड़ना था। धैर्य के साथ वे अपनी बात रखते रहे और आखिरकार बदलाव की बग्यार बही। बकौल भूमिका, 'नेपाली समाज में थर्ड जेंडर की अब अधिक स्वीकृति है।' अपनी नागरिकता पहचान-पत्र में थर्ड जेंडर की शिनाख्त के लिए उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी, 2007 में नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया। अदालत ने साफ कहा कि एक नागरिक की पहचान थर्ड जेंडर के रूप में हो सकती है। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद भूमिका के नागरिकता पहचान-पत्र पर उनकी असली लैंगिक पहचान दर्ज हुई। इस कामयाबी ने उन्हें नई उड़ान भरने का आत्मविश्वास दिया। वह पहली नेपाली नागरिक हैं, जिन्होंने पासपोर्ट पर थर्ड जेंडर पहचान के साथ विदेश की उड़ान भरी। उनकी टीम इस वर्ग के 35 हजार लोगों की मदद कर चुकी है। बचपन से ही नृत्य-निर्देशक बनने के ख्याल सजोने वाली भूमिका ने आखिरकार कला के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। कई डॉक्यूमेंट्री बना चुकी भूमिका नेपाली फिल्मों में भी अभिनय करती हैं। साल 2010 से वह नेपाली कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं। कोरोना महामारी के दौरान पिछले साल उन्होंने अपने समुदाय को सरकार से काफी राहत दिलाई थी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, उस समय भारत में इस समुदाय के लगभग पांच लाख लोग थे। उन्हें देश की अदलिया ने तमाम सांविधानिक अधिकार दिए हैं, मगर समाज ने उन अधिकारों का कभी दिल से सम्मान नहीं किया। इसके लिए इस समुदाय को अभी काफी लंबी लड़ाई लड़नी है। ऐसे में, इस वर्ग की जंग में जस्टिन टूडेव, जो बाइडन जैसे अधिकार संपन्न राजनेताओं के प्रयास तो सराहनीय है ही, भूमिका श्रेष्ठ जैसा का संघर्ष भी कम वंदनीय नहीं। प्रस्तुति - चंद्रकांत सिंह

सू-दोकू नवताल - 2105

7	4	6	1	8	2	
5	8	7				
9		6				
6	7	9	5	3		
5		4			1	
3	1	8	2	7		
		5			6	
		4	3		9	
4	3		2	1	5	7

सू-दोकू 2104 का हल

8	7	9	4	2	5	6	1	3
5	6	3	8	1	7	4	2	9
4	1	2	6	9	3	5	8	7
1	9	8	3	7	4	2	6	5
7	3	4	2	5	6	8	9	1
2	5	6	1	8	9	7	3	4
9	8	5	7	3	2	1	4	6
6	2	7	9	4	1	3	5	8
3	4	1	5	6	8	9	7	2

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3 x 3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।

बारें से दारें:-

- 'वादियों मेरा दामन' गीत वाली फिल्म-4
- 'बेचारा दिल क्या करे' गीत वाली जीतेन्द्र, हेमा, शर्मिला की फिल्म-3
- संजय दत्त, काजोल की 'प्यार को हो जाने दो' गीत वाली फिल्म-2
- 'मुसाफिर हूँ यारो' गीत वाली संजय कुमार, जया भादुड़ी की फिल्म-4
- रणधीर कपूर, रेखा की 'दिल मचल रहा है' गीत वाली फिल्म-3
- 'फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत' में ईशा नारय की भूमिका किसने की है-2
- संजय कपूर, माधुरी की 'फूल मांगूँ ना बहार मांगूँ' गीत वाली फिल्म-2
- 'लम्हा लम्हा टूट गए' गीत वाली सोहेल खान, श्रेया की फिल्म-3
- नवीन, आशा पारेख की 'ऐ बादल झूम के चल' गीत वाली फिल्म-3
- 'खुल गया नसीब देखो साला' गीत वाली सुनील शेट्टी, पूजा बत्रा की फिल्म-2
- विश्वजीत, बबिता की 'आंखों में क्यामत के काजल' गीत वाली फिल्म-3
- 'तुझे रब ने बनाया है कमाल' गीत वाली आमिर, फैजल खान, दिव्यंका खन्ना की फिल्म-2
- संजय दत्त, माधुरी दीक्षित की 'टपका रे टपका' गीत वाली फिल्म-4
- 'आ जा रे ओ मेरे दिलवर आज' गीत वाली फाराख शेख, पूनम दिल्लों की फिल्म-2
- फिल्म 'अग्निपथ' में मिथुन चक्रवर्ती के किरदार का नाम क्या था-2
- सनी, त वू, रीमा सेन की 'एक लड़की बस गई' गीत वाली फिल्म-2
- 'दिन सारा गुजारा' गीत वाली शम्मी कपूर, सावरा बानो की फिल्म-3
- 'आधा है चंद्रमा रात आधी' गीत वाली महिपाल, संध्या की फिल्म-3
- धर्मेन्द्र, जिनत अमान की 'हम बेवफा हरगिज न थे' गीत वाली फिल्म-4

फिल्म वर्ग पहेली-2105

1	2	3	4	5	
		6			
7		8		9	10
		11	12		
	13		14	15	16
17			18	19	
		20		21	22
23		24		25	
26	27		28		29
30				31	

ऊपर से नीचे:-

- 'जानू दे नशा है' गीत वाली फिल्म-2
- दिलीप कुमार, शर्मिला टैगोर की 'एक तो ये बैरी सावन' गीत वाली फिल्म-3
- 'कुतों को बर्दों को' गीत वाली दिलीप कुमार, रेखा, ममता कुल्कर्णी की फिल्म-2
- शरद कपूर, पूजा भट्ट की 'भर से मस्जिद' गीत वाली फिल्म-3
- 'बोल येको बोल' गीत वाली फिल्म-2,2
- विकास भल्ला, काजोल की 'मेरे चेहरे पे लिखा है' गीत वाली फिल्म-3
- 'गर तुम भूला ना दोगे सपने ये सच हो होंगे' गीत वाली धर्मेन्द्र, शर्मिला टैगोर की फिल्म-3
- नासिर खान, मधुबाला की 'ऐ चांद प्यार मेरा तुझसे ये कह रहा' गीत वाली फिल्म-3
- 'तुम रुठ के मत जाना' गीत वाली भारतभूषण, मधुबाला की फिल्म-3
- जैकी श्रॉफ, जूही, अमृता सिंह की 'गोरिया रे गोरिया रे मेरा दिल चुराके' गीत वाली फिल्म-3
- 'हे इसी में प्यार को आबरू' गीत वाली धर्मेन्द्र, माला सिन्हा की फिल्म-4
- विनोद मेहरा, धिंदिया गोव्यामो की 'जिसे जलकों की हसरत हो' गीत वाली फिल्म-3
- 'बनो तेरी अंखियां' गीत वाली सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोहरला की फिल्म-3
- 'बिखर जाने को' गीत वाली फिल्म-3
- 'गर तुम भूला ना दोगे सपने ये सच हो होंगे' गीत वाली धर्मेन्द्र, शर्मिला टैगोर की फिल्म-3
- नासिर खान, मधुबाला की 'ऐ चांद प्यार मेरा तुझसे ये कह रहा' गीत वाली फिल्म-3
- 'तुम रुठ के मत जाना' गीत वाली भारतभूषण, मधुबाला की फिल्म-3
- जैकी श्रॉफ, जूही, अमृता सिंह की 'गोरिया रे गोरिया रे मेरा दिल चुराके' गीत वाली फिल्म-3



अप्रैल में थोक बिक्री में छह फीसदी पिछड़ी मारुति सुजुकी

-बिक्री घटकर 1,50,661 इकाई पर पहुंची

नई दिल्ली । आम आदमी का कार कहलाने वाली देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की थोक बिक्री अप्रैल, 2022 में छह प्रतिशत घटकर 1,50,661 इकाई रह गई। अप्रैल, 2021 में कंपनी ने 1,59,691 वाहन बेचे थे। कंपनी ने रिविवा को एक बयान में कहा कि अप्रैल में घरेलू बाजार में उसकी बिक्री सात प्रतिशत घटकर 1,32,248 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 1,42,454 इकाई थी। समीक्षाधीन महीने में कंपनी की छेटी कारों- आल्टो और एस-प्रेंसो की बिक्री 32 प्रतिशत घटकर 25,041 से 17,137 इकाई पर आ गई। इसी तरह कॉम्पैक्ट खंड में कंपनी की बिक्री 18 प्रतिशत घटकर 59,184 इकाई रह गई। इस खंड में कंपनी स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर जैसे मॉडल बेचती है। अप्रैल, 2021 में इस खंड में कंपनी की बिक्री 72,318 इकाई रही थी। मध्यम आकार की सेडान सिराज की बिक्री अप्रैल, 2021 के 1,567 इकाई के आंकड़े से घटकर 579 इकाई रह गई। हालांकि, यूटिलिटी वाहनों मसलन विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एल्टो की बिक्री 33 प्रतिशत के उछाल से 33,941 इकाई पर पहुंच गई, जो एक साल पहले समान महीने में 25,484 वाहन रही थी। अप्रैल में कंपनी का निर्यात सात प्रतिशत बढ़कर 18,413 इकाई पर पहुंच गया, जो एक साल पहले समान महीने में 17,237 इकाई रहा था।

कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 100 रुपए महंगा

नई दिल्ली । कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में महीने के पहले ही दिन बढ़ोतरी हो गई है तो किन फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत मिली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर में 1 मई से 100 रुपए से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। अभी पिछले महीने एक अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा हुआ था। वहीं 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर 655 रुपए में मिल रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली के लोगों को 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिए 2355.50 रुपए भुगतान करने होंगे। इससे पहले 2253 रुपए ही लगते थे। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 2351 रुपए से बढ़कर 2455 रुपए हो गई है। मुंबई में 2205 रुपए की जगह 2307 रुपए अब खर्च करने होंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़कर 2406 रुपए की जगह 2508 रुपए हो गई हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 949.5 रुपए है। इसके अलावा कोलकाता में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 976 रुपए, मुंबई में 949.50 रुपए और चेन्नई में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब 965.50 रुपए है। वहीं लखनऊ में घरेलू रसोई गैस की कीमत 987.50 रुपए है, जबकि पटना में 14.2 किलो के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1039.5 रुपए है।

सेबी के नए दिशानिर्देश नौ मई से लागू होंगे

नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने विदेशी निवेशकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं उनके नाम में बदलाव से संबंधित डिफॉजंटरी प्रतिभागियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के परिचालन दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव किए हैं। सेबी ने जारी एक परिपत्र में इन बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा है कि नए दिशानिर्देश नौ मई से लागू होंगे। सेबी के परिपत्र के अनुसार, एफपीआई के पंजीकरण के प्रमाण पत्र और उनके नाम में बदलाव से संबंधित द्वांचे को संशोधित किया गया है। एफपीआई के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंध में नामित डिफॉजंटरी प्रतिभागी (डीडीपी) पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिस पर सेबी की तरफ से जारी पंजीकरण संख्या का उल्लेख होगा। सेबी ने कहा कि किसी एफपीआई के नाम में बदलाव होने की स्थिति में डीडीपी ऐसा अनुरोध मिलने के बाद प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन करेगा। इसके पहले जनवरी में सेबी ने एफपीआई पंजीकरण संख्या के सृजन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। उसके बाद वित्त मंत्रालय ने मार्च में कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (सीएफ) में संशोधन किया।

ईडी के छापे के बाद शाओमी बोलो- कंपनी में सभी काम नियम-कानूनों के तहत होते हैं

नई दिल्ली ।

चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापामार कार्रवाई में 5,551 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के बाद कंपनी ने बयान जारी कर सफाई दी है। बयान में कहा गया है कि कंपनी एक प्रतिबद्ध ब्रांड के रूप में भारत के लिए पूरी तरह समर्पित है। बकाल शाओमी, 'हमारे सभी कार्य भारतीय नियम और कानूनों के दृढ़ पालन के तहत होते हैं।'

शाओमी ने कहा है कि कंपनी ने सरकारी अधिकारियों के आदेश का अध्ययन किया है और उनके द्वारा बैंक को दिए विवरण व रॉयल्टी भुगतान सत्य और वैध हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है, 'शाओमी इंडिया द्वारा किए

गए रॉयल्टी भुगतान लाइसेंस प्राप्त तकनीकों और हमारे उत्पादों के भारतीय वर्जन में इस्तेमाल किए जाने वाले आईपी के लिए थे। शाओमी इंडिया एक वैध वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत यह भुगतान करती है।'

हालांकि, हम किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए अधिकारियों से बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईडी ने एक बयान जारी कर कहा है कि कंपनी गोरखधंधे में लिप्त है और विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इससे पहले ईडी अवैध रिमोट्स के मामले में जांच शुरू की थी।

ईडी कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन को भी तलब कर चुकी है। खबर के अनुसार, शाओमी ने जिन 3 कंपनियों को

रॉयल्टी दी है उनसे कोई सेवा नहीं ली है। इन तीन कंपनियों में 1 शाओमी समूह की इकाई है जबकि बाकी 2 कंपनियां यूएस आधारित संस्थानों से जुड़ी हैं। इससे मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह पैदा हुआ है। कंपनी पर आरोप है कि वह अवैध रूप से कमाई गई रकम देश से बाहर भेज रही है। इसके अलावा कंपनी ने फेमा का उल्लंघन करते हुए करोड़ों रुपये का निवेश भारत में किया है।

शाओमी भारत में एमआई या रेडमी ब्रांड नाम के साथ करोबार करती है। कंपनी ने 2014 में भारत में अपना बिजनेस शुरू किया था। यह पूरी तरह से चीनी स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी ने भारत में करोबार शुरू करने के अगले साल यानी 2015 से पैसा बाहर भेजना शुरू कर दिया था।

बिजली संयंत्रों के पास कोयले का अपेक्षित भंडार, सुनिश्चित करना कोल इंडिया की प्राथमिकता : प्रमोद अग्रवाल

नई दिल्ली । कोयले की कमी और बिजली किल्लत के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया ने कहा कि ताप ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति करना उसकी 'प्राथमिकता' है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों से चालू वित्त वर्ष में 70 करोड़ टन के कोयला उत्पादन और उद्योग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने को कहा है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने कर्मचारियों को भेजे पत्र में कहा कि कंपनी की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बिजली की कमी के बीच बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों के पास घरेलू

ईंधन का पर्याप्त भंडार हो। अग्रवाल ने कर्मचारियों से कहा कि वे इसे 'पावन' लक्ष्य मानें। उन्होंने कहा, 'कोल इंडिया की प्राथमिकता है कि देश के बिजली संयंत्रों में घरेलू कोयले का पर्याप्त भंडार हो और देश को उचित दामों पर बिजली मिले। हमारा लक्ष्य ऊर्जा को कम से कम कीमत पर सुनिश्चित करने का होना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'बीते वित्त वर्ष के प्रदर्शन से प्रेरणा लें और 70 करोड़ टन उत्पादन तथा उद्योग के लक्ष्य को पूरा करें।' कंपनी की ओर से 2021-22 में ऊर्जा क्षेत्र को आपूर्ति 54.04 करोड़ टन के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई थी। तब कंपनी का कोयला उद्योग भी



66.2 करोड़ टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2020-21 के मुकाबले 15.3 फीसदी अधिक था।

इस सप्ताह वैश्विक रुख का बाजार पर रहेगा असर

मुंबई । बीते सप्ताह उतार-चढ़ाव के बाद गिरावट की मार झेल चुके घरेलू शेयर बाजार पर बढ़ती महंगाई और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से अमेरिकी फेड रिजर्व ओपन मार्केट कमेट्री (एफओएमसी) के रुख एवं वैश्विक स्तर पर जारी होने वाले पीएमआई का अगले सप्ताह बाजार पर असर रहेगा। बाजार के जानकारों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट पर रहा। हालांकि बाजार सीमित दायरे में रहा लेकिन कंपनियों के समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही की आय के आंकड़ों का बाजार पर असर रहा। अमेरिकी बाजार में तेज गिरावट के बाद अगले सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में मंदी की शुरुआत होने की संभावना है। वहीं, अमेरिकी एफओएमसी बैठक के नतीजे, जो रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और विकास चिंताओं के बीच महत्वपूर्ण है पर निवेशकों की नजर रहेगी। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि एफओएमसी की बैठक बुधवार को होनी है और घरेलू बाजार पर गुरुवार को इसका असर देखा जा सकेगा। इस सप्ताह एफओएमसी बैठक के अलावा बीओई ब्याज पर निर्णय, अमेरिका में रोजगार के आंकड़े विश्वव्यापी पीएमआई आंकड़े जारी किए जाएंगे। इन वैश्विक कारकों का शेयर बाजार की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही कमांडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, डॉलर इंडेक्स और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) का व्यवहार भी बाजार को प्रभावित करने वाले अग्र प्रमुख कारक बने रहेंगे। स्थानीय स्तर पर अगले सप्ताह अप्रैल में वाहनों की बिक्री के साथ ही रिलायंस, ब्रिटानिया, एचडीएफसी लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेज, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, टाइटन, कोटक महिंद्र बैंक और टाटा पावर जैसी दिग्गज कंपनियों की चौथी तिमाही के वारि होने वाले आंकड़ों का भी बाजार पर असर रहेगा।

एलआईसी आईपीओ काउंटडाउन शुरू, एक नहीं तीन वर्गों में कर सकते हैं अप्लाई

नई दिल्ली ।

शेयर बाजार में देश के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित आईपीओ एलआईसी को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एलआईसी का आईपीओ 4 मई को खुलेगा। शेयर खरीदने के लिए 9 मई तक आवेदन किया जा सकता है। एलआईसी आईपीओ का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 15 शेयर रखे गए हैं। निवेशक कम से कम एक और अधिकतम 14 लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए इन आईपीओ में निवेश करने के लिए कम से कम 14,235 रुपये और अधिकतम 1,99,290 रुपये की जरूरत होगी। सरकार ने एलआईसी की पॉलिसीधारकों के लिए 60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर छूट देने की बात कही है। इस छूट के लिए केवल वही एलआईसी पॉलिसीधारक पात्र होंगे, जिन्होंने 13 अप्रैल, 2022 या इससे पहले एलआईसी की कोई पॉलिसी खरीदी है।

पॉलिसीधारकों के लिए आईपीओ में 15 परसेंट का रिजर्वेशन रखा गया है। एलआईसी कर्मचारियों को 45 रुपये प्रति इक्विटी शेयर छूट दी जाएगी। इस आईपीओ को लेकर एलआईसी पॉलिसीधारकों में खासा क्रेंज देखने को मिल रहा है। लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपल) के अनुसार, करीब 6.48 करोड़ पॉलिसी धारकों ने अपने पैन नंबर को पॉलिसी डिटेल के साथ जोड़ा है। इस आईपीओ के माध्यम से सरकार एलआईसी की अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी को बेच रही है। इसके माध्यम से सरकार ने 21,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का टारगेट तय किया है। यह भारतीय बाजार में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। कई निवेशक ऐसे ही हैं जो एलआईसी के कर्मचारी हैं और उनके पास इसकी पॉलिसी भी है। कुछ लोग पॉलिसीहोल्डर होने के साथ-साथ रिटेल निवेशक भी हो सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि कोई व्यक्ति रिटेल और पॉलिसी होल्डर, दोनों की कैटेगरी में आईपीओ के लिए



आवेदन कर सकता है। इस तरह उसे अधिकतम 4 लाख रुपये निवेश करने होंगे। और इस तरह एलआईसी का कर्मचारी तीन कोटे (पॉलिसी होल्डर और रिटेल के साथ) में आवेदन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 6 लाख रुपये निवेश करने होंगे। आईपीओ की लॉन्चिंग से पहले एलआईसी का ग्रे मार्केट प्रीमियम- जीएमपी बढ़ता जा रहा है। शनिवार को एलआईसी आईपीओ का जीएमपी 92 रुपये हो गया। जीएमपी से अंदाजा लगाया जाता है कि शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक की लिस्टिंग किस भाव पर हो सकती है।

सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला

नई दिल्ली । जानेमाने अर्थशास्त्री और शोध प्रशासक सुमन बेरी ने रविवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बेरी इससे पहले नेशनल कार्सिल ऑफ एप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर) के महानिदेशक (मुख्य कार्यकारी) और रॉयल डच शेल के वैश्विक मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। सरकार के शोध संस्थान नीति आयोग में आने से पहले वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकी आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। बयान में कहा गया है नीति आयोग एक मई से सुमन बेरी का उपाध्यक्ष के रूप में स्वागत करता है। बेरी ने नीति आयोग में राजीव कुमार का स्थान लिया है। राजीव कुमार ने अगस्त, 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभाला था। उन्होंने अखिल पनगढ़िया का स्थान लिया था। बेरी ने कहा कि कुमार ने मेरे लिए एक ऐसा संगठन छोड़ा है जिसमें काफी युवा शामिल हैं। उनका सरकार के अंदर और बाहर के हितधारकों से मजबूत संबंध है।

विमान ईंधन के दाम रिकॉर्ड बढ़ोतरी, एटीएफ कीमतों में 3.22 प्रतिशत का इजाफा

-चार महीने में नौवीं बार रेटों में हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली ।

महंगाई की मार से विमान ईंधन (एटीएफ) भी बच नहीं सका उसकी कीमतों में 3.22 प्रतिशत की और वृद्धि की गई है। इससे इसके दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस साल यानी 2022 में विमान ईंधन कीमतों में यह नौवीं बढ़ोतरी है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर विमान ईंधन पर भी पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोिलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमतों में 3,649.13 रुपये प्रति किलोलिटर या 3.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अब राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ का दाम 1,16,851.46 रुपये प्रति किलोलिटर (116.8 रुपये लीटर) पर पहुंच गया है। इस बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 25वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले वाहन ईंधन के दामों में रिकॉर्ड 10-10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। विमान ईंधन की कीमतों में हर महीने की पहली और

16 तारीख को संशोधन किया जाता है। वहीं पेट्रोल और डीजल कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दामों के अनुरूप प्रतिदिन संशोधन होता है। इससे पहले 16 मार्च को एटीएफ के दाम 18.3 प्रतिशत या 17,135.63 रुपये प्रति किलोलिटर बढ़ाए गए थे। वहीं एक अप्रैल को भी विमान ईंधन दो प्रतिशत या 2,258.54 रुपये प्रति किलो लीटर महंगा हुआ था। 16 अप्रैल को इसकी कीमतों में मामूली 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मुंबई में एटीएफ का दाम अब 1,15,617.24 रुपये प्रति किलोलिटर हो गया है। कोलकाता में यह 1,21,430.48 रुपये और चेन्नई में 1,20,728.03 रुपये प्रति किलोलिटर हो गया है। स्थानीय करों की वजह से विभिन्न राज्यों में



एटीएफ का दाम अलग-अलग होता है। किसी भी एयरलाइन की परिचालन लागत में विमान ईंधन का हिस्सा करीब 40 प्रतिशत होता है। 2022 की शुरुआत से एटीएफ का दाम हर पखवाड़े में बढ़ता गया है। एक जनवरी से नौ बार में एटीएफ कीमतों में 42,829.55 रुपये प्रति किलोलिटर या 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने के लिए फॉर्म अधिसूचित

नई दिल्ली । आयकर विभाग ने अद्यतन (अपडेटेड) आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए एक नया फॉर्म अधिसूचित किया है। इसमें करदाताओं को इसे दाखिल करने की सही वजह के साथ यह भी बताना होगा कि कर के लिए कितनी राशि को पेश किया जा रहा है। नया फॉर्म (आरटीआर-यू) करदाताओं को वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध होगा। आईटीआर-यू दाखिल करने वाले करदाताओं को आय को अद्यतन करने के लिए कारण देना होगा। उन्हें इसकी वजह बतानी होगी कि पहले रिटर्न दाखिल क्यों नहीं किया गया, या आय की सही जानकारी क्यों नहीं दी गई। यह फॉर्म संबद्ध आकलन वर्ष के अंत के दो साल के भीतर दाखिल किया जा सकता है। आम बजट 2022-23 में करदाताओं को आईटीआर को दाखिल करने के दो साल के भीतर उसे अपडेट करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, इस अनुमति से पहले करों का भुगतान जरूरी होगा। इस कदम का मकसद आईटीआर में हुई गलती या कोई जानकारी छूटने पर उसमें सुधार का मौका देना है।

विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में भारतीय बाजारों से 17,144 करोड़ निकाले



नई दिल्ली । भारतीय बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की निकासी अप्रैल में लगातार सातवें महीने जारी रही। अमेरिकी के द्वायी बैंक द्वारा आक्रामक तरीके से ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका के बीच एफपीआई ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजारों से 17,144 करोड़ रुपए निकाले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अलावा निफ्टो भविष्य में धारणा में उतार-चढ़ाव कायम रहेगा। वैश्विक स्तर पर आक्रामक दरों से ब्याज दरों में बढ़ोतरी तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से धारणा प्रभावित रहेगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अप्रैल तक बिक्राल रह रहे हैं और उन्होंने शेयरों से 1.65 लाख करोड़ रुपए की भारी राशि निकाली है। इसकी प्रमुख वजह अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की आशंका के हमले के बाद पैदा हुआ छू-राजनीतिक संकट है। लगातार धूम महीने की बिक्रवाली के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में

एफपीआई शुद्ध लिवाब रहे थे और उन्होंने 7,707 करोड़ रुपए का निवेश किया था लेकिन उसके बाद कम कारोबारी सत्रों वाले सप्ताह 11 से 13

अप्रैल के दौरान उन्होंने फिर बिक्रवाली की। उसके बाद के हफ्तों में भी उनका बिक्रवाली का सिलसिला जारी रहा। डिफॉजंटरी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में एफपीआई ने भारतीय बाजारों से 17,144 करोड़ रुपए निकाले हैं। हालांकि, यह मार्च के 41,123 करोड़ रुपए की निकासी के आंकड़े से कम है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मई में ब्याज दरों में आधा प्रतिशत की वृद्धि का संकेत दिया है।

यह एक प्रमुख वजह है कि एफपीआई भारतीय बाजारों से निकासी कर रहे हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि एफपीआई अप्रैल में शुद्ध बिक्रवाल बने रहे। इसकी प्रमुख वजह फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक तरीके से बढ़ोतरी की आशंका है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की आशंका ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है। इसकी वजह से निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और वे भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश को लेकर देखे और इंतजार करे की नीति अपना रहे हैं।

सैंसेक्स की पांच प्रमुख कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 67,843 करोड़ बढ़ा

सबसे अधिक लाम में हिंदुस्तान यूनिटीवर लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज रही

नई दिल्ली । बीते सप्ताह सेंसेक्स की प्रमुख 10 में से पांच कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में 67,843.33 करोड़ रुपए बढ़ा। सबसे अधिक लाभ में हिंदुस्तान यूनिटीवर लिमिटेड (एचयूएल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। बीते सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिटीवर, भारती एयरटेल और एचडीएफसी के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई।

वहीं दूसरी ओर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, अडाणी ग्रीन एनर्जी और भारतीय स्टैट बैंक (एसबीआई) के बाजार मूल्यांकन में गिरावट आई। समीक्षाधीन सप्ताह में हिंदुस्तान यूनिटीवर का बाजार पूंजीकरण 25,234.61 करोड़ रुपए बढ़कर 5,25,627.06 करोड़ रुपए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 21,892.61 करोड़ रुपए के उछाल के साथ 18,87,964.18 करोड़ रुपए, एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 16,251.27

करोड़ रुपए बढ़कर 7,68,052.87 करोड़ रुपए, एचडीएफसी की 3,943.09 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 4,03,969.09 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने सप्ताह के दौरान 521.75 करोड़ रुपए जोड़े और उसका बाजार पूंजीकरण 4,06,245.26 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

इसके विपरीत टीसीएस की बाजार हैसियत 22,594.64 करोड़ रुपए घटकर 12,98,999.83 करोड़ रुपए, इन्फोसिस का बाजार मूल्यांकन 7,474.58 करोड़ रुपए टूटकर 6,59,587.97 करोड़ रुपए, एसबीआई के बाजार पूंजीकरण में 3,480.6 करोड़ रुपए की गिरावट आई और यह 4,43,106.96 करोड़ रुपए पर आ गया, आईसीआईसीआई बैंक की बाजार हैसियत 2,600.14 करोड़ रुपए घटकर 5,16,762.48 करोड़ रुपए और अडाणी ग्रीन का बाजार मूल्यांकन 172.04 करोड़ रुपए के नुकसान से 4,51,577.84 करोड़ रुपए रह गया।

अप्रैल से जून में एप्पल को चीन में 61,000 करोड़ का नुकसान

सैन फ्रांसिस्को । चीन में कोविड-19 की वजह से लोकडाउन चल रहा है। ऐसे में अमेरिकी टेक कंपनी ऐपल को जोरदार नुकसान उठाना पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान कंपनी ने 8 बिलियन डॉलर (61,000 करोड़ रुपए) के नुकसान का अनुमान जताया है। गौरतलब है कि चीन के सबसे बड़े शहरों में से एक शंघाई में पिछले 2 माह से लोकडाउन लगा है। साथ ही चीन के कई अन्य बड़े शहरों में कोविड प्रतिबंध जारी है। ऐसे में ऐपल के

उत्पादों की मांग में कमी दर्ज की जा रही है। ऐपल के सीईओ टिम कुम ने अनुमान जाहिर किया है कि चीन में लगे लोकडाउन की वजह से कंपनी को 4 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। कोविड-19 प्रतिबंध की वजह से ग्राहकों की मांग में कमी दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट की मांग तो ऐपल की 200 से ज्यादा मेन सप्लायर फैसिलिटी शंघाई के चारों तरफ मौजूद है। ऐपल को आईफोन निर्माण के लिए इंडस्ट्री वाइड सिलिकॉन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिसका असर



भी इस तिमाही में दिख रहा है। भारत सरकार की कौशिश है कि ऐपल चीन पर अपनी निर्भरता कम करे। इस योजना के तहत ऐपल भारत में निर्माण में पर जो दे रही है। ऐपल ने हाल ही में आईफोन 12 का निर्माण शुरू कर दिया है। जबकि हाल ही में आईफोन 13 का विनिर्माण शुरू किया है। ऐसे में पिछले एक साल के मुकाबले भारत में ऐपल के विनिर्माण में 50 फीसदी का उछाल देखा गया है। बता दें कि

केंद्र सरकार भारत को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से घरेलू स्तर पर स्मार्टफोन निर्माण के लिए पीएलआई स्क्रीम शुरू की है।

अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किये जाते हैं, उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी बारह महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किन्तु वैशाख माह की तिथि स्वयंसिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है।

महत्व

अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह-प्रवेश, वस्त्र-आभूषणों की खरीददारी या घर, भूखण्ड, वाहन आदि की खरीददारी से सम्बन्धित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उदघाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिन्डदान अथवा किसी और प्रकार का दान, अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप-तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने-अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सदगुण प्रदान करते हैं, अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सदगुणों का वरदान माँगने की परम्परा भी है।

हिन्दू धर्म में महत्व

अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शान्त चित होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ या गेहूँ का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात् फल, फूल, बरतन, तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि वसन्त ऋतु के अन्त और ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ का दिन भी है इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खडाऊँ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गरमी में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन-जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा, वे समस्त वस्तुएँ स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद कमल अथवा सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करना चाहिये।

‘सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदावर्तन।

दानकाले च सर्वत्र मन्त्र मेत मुदीरयेत्॥’

अर्थात् सभी महीनों की तृतीया में सफेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है।

भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है, सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर-नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्माजी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृन्दावन स्थित श्री बाँके बिहारी जी मन्दिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। जी.एम. हिंगे के अनुसार तृतीया 41 घटी 21 पल होती है तथा धर्म सिन्धु एवं निर्णय सिन्धु ग्रन्थ के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घटी से अधिक होना चाहिए। पञ्च पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराद्ध व्यापिनी मानना चाहिए। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारम्भ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता। मदनरत्न के अनुसार :



‘अस्यां तिथौ क्षयमुपति हुतं न दत्तं। तेनाक्षयेति कथिता मुनिभिस्तृतीया॥
उद्धिद्य दैवतपितृत्क्रियते मनुष्यैः। तत् च अक्षयं भवति भारत सर्वमेव॥’

प्रचलित कथाएँ

अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएँ प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात् उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी-देवताओं की पूजा की, व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएँ ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म-कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदशे तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेष धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमण्ड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयन्ती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयन्ती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयन्ती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियों और कारी कन्याएँ इस दिन गौरी-पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बाँटती हैं, गौरी-पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया था। जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर संन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे तभी उनका नाम परशुराम पड़ा।

जैन धर्म में अक्षय-तृतीया

तीर्थंकर आदिनाथ को प्रथम आहार देते राजा श्रेयांस (चित्र-अजमेर जैन मन्दिर) जैन धर्मावलम्बियों का महान धार्मिक पर्व है। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान ने एक वर्ष की पूर्ण तपस्या करने के पश्चात् इक्षु (शोरडी-गन्ने) रस से पारायण किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने सत्य व अहिंसा का प्रचार करने एवं अपने कर्म बन्धनों को तोड़ने के लिए संसार के भौतिक एवं पारिवारिक सुखों का त्याग कर जैन वैराग्य अंगीकार कर लिया। सत्य और अहिंसा के प्रचार करते-करते आदिनाथ प्रभु हस्तिनापुर गजपुर पधारे जहाँ

भगवान परशुराम के जीवन से जुड़े पौराणिक किस्से

कृष्ण प्रसिद्ध रामायण कथाओं के मुख से कई बार यह सुनाई देता है कि परशुराम क्रोधी थे, जनकपुर में धनुष भंजन के बाद जब वह यज्ञ शाला में पहुँचे तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। लक्ष्मण ने उन्हें खूब छकाया, जब भगवान श्री राम ने उनके धनुष में तीर का संधान किया तो राम के सम्मुख नतमस्तक होकर चले गए आदि-आदि। परशुराम दशावतारों में हैं। क्या उन्हें इतना भी आभास नहीं होगा कि यह धनुष किसने तोड़ा? क्या वह साधारण पुरुष हैं? श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने के बाद समस्त राजाओं की दुरभिसंधि हुई कि श्री राम ने धनुष तोड़ लिया है, लेकिन इन्हें सीता स्वयंवर से रोकना होगा। वे अतः अपनी-अपनी सेनाओं की टुकड़ियों के साथ धनुष यज्ञ में आए समस्त राजा एकजुट होकर श्री राम से युद्ध के लिए कर्म कर तैयार हो गए। धनुष यज्ञ गृह युद्ध में बदलने वाला था, ऐसी विकट स्थिति में वहाँ अपना फरसा लहराते हुए परशुराम जी प्रकट हो गए। वे राजा जनक से पूछते हैं कि तुरंत बताओ कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है, अन्यथा जितने राजा यहाँ बैठे हैं... मैं क्रमशः उन्हें अपने परशु की भेंट चढ़ाता हूँ। तब श्री राम विनम्र भाव से कहते हैं- हे नाथ शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। परशुराम-राम संवाद के बीच में ही लक्ष्मण उत्तेजित हो उठे, विकट लीला प्रारंभ हो गई। संवाद चलते रहे लीला आगे बढ़ती रही परशुराम जी ने श्री राम से कहा अच्छा मेरे विष्णु धनुष में तीर चढ़ाओ... तीर चढ़ गया, परशुराम जी

ने प्रणाम किया और कहा मेरा कार्य अब पूरा हुआ, आगे का कार्य करने के लिए श्री राम आप आ गए हैं। गृह युद्ध टल गया। सारे राजाओं ने श्री राम को अपना सम्राट मान लिया, भेंट पूजा की एवं अपनी-अपनी राजधानी लौट गए। श्री राम के केंद्रीय शासन नियमों से धर्मयुक्त राज्य करने लगे। देश में शांति छाने लगी अब श्री राम निश्चित थे क्योंकि उन्हें तो देश की सीमाओं के पार से संचालित आतंक के खिलाफ लड़ना था, इसीलिए अयोध्या आते ही वन को चले गए। पंचवटी में लीला रची गई, लंका कूच हुआ। रावण का कुशासन समाप्त हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई। अतः राम राज्य की स्थापना की भूमिका तैयार करने वाले भगवान परशुराम ही थे।

भगवान परशुराम के किस्से- भगवान परशुराम राम के काल में भी थे और कृष्ण के काल में भी उनके होने की चर्चा होती है। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक वे धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरि पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्यांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। जानिए परशुराम के किस्से -
- जब एक बार गणेशजी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो, रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एकदंत कहलाए।
- जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिर्नंदन किया।



खुदा का इनाम, खुशियों का गुलदस्ता और रौनक का जश्न है ईद उल-फ़ित्र

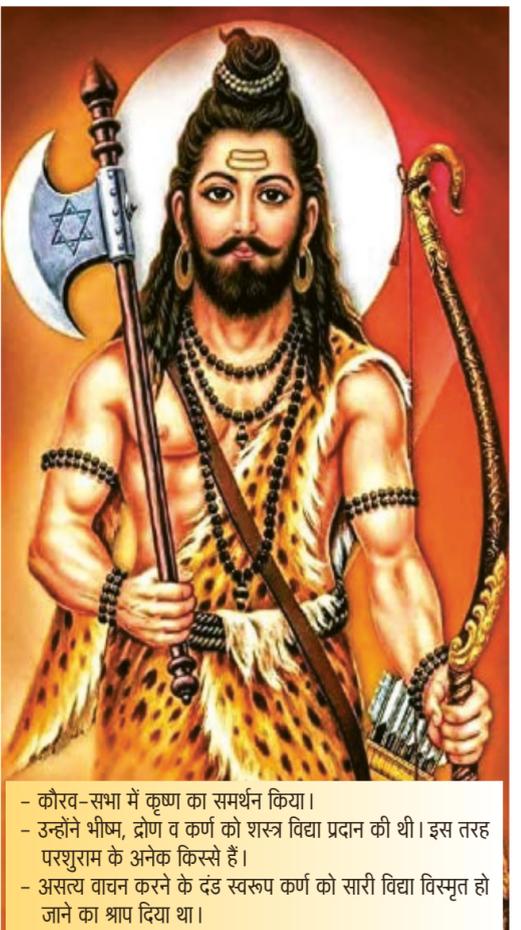
रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है। इस पूरे माह में रोजे रखे जाते हैं। इस महीने के खत्म होते ही दसवां माह शव्वाल शुरू होता है। इस माह की पहली चांद रात ईद की चांद रात होती है। इस रात का इंतजार वर्ष भर खास वजह से होता है, क्योंकि इस रात को दिखने वाले चांद से ही इस्लाम के बड़े त्योहार ईद उल-फ़ित्र का ऐलान होता है। इस तरह से यह चांद ईद का पैगाम लेकर आता है। इस चांद रात को अल्फा कहा जाता है।

रमजान माह की इबादतों और रोजे के बाद जलवा अफरोज हुआ ईद उल-फ़ित्र (ईद-उल-फ़ितर) का त्योहार खुदा का इनाम है, मुसरतों का आगाज है, खुशखबरी की महक है, खुशियों का गुलदस्ता है, मुस्कुराहटों का मौसम है, रौनक का जश्न है। इसलिए ईद का चांद नजर आते ही माहौल में एक गजब का उल्लास छा जाता है।

ईद के दिन सिवइयों या शीर-खुरम से मुंह मीठा करने के बाद छोट-बड़े, अटने-पराए, दोस्त-दुश्मन गले मिलते हैं तो चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। एक पवित्र खुशी से दमकते सभी चेहरे इंसानियत का पैगाम माहौल में फैला देते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगते व रमजान के रोजे और इबादत की हिम्मत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हाथ हर तरफ दिखाई पड़ते हैं और यह उत्साह बयान करता है कि

लो ईद आ गई। कुरआन के अनुसार पैगंबरे इस्लाम ने कहा है कि जब अहले ईमान रमजान के पवित्र महीने के एहतेरामों से फारिग हो जाते हैं और रोजों-नमाजों तथा उसके तमाम कामों को पूरा कर लेते हैं, तो अल्लाह एक दिन अपने उक्त इबादत करने वाले बंदों को बख्शीश व इनाम से नवाजता है। इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं और इसी बख्शीश व इनाम के दिन को ईद-उल-फ़ितर (ईद-उल-फ़ित्र) का नाम देते हैं।

रमजान माह के रोजे को एक फर्ज करार दिया गया है, ताकि इंसानों को भूख-प्यास का महत्व पता चले। भौतिक वासनाएं और लालच इंसान के वजूद से जुदा हो जाए और इंसान कुरआन के अनुसार अपने को ढाल लें। इसलिए रमजान का महीना इंसान को अशरफ और आला बनाने का मौसम है। पर अगर कोई सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करे और उसके बंदों से मोहब्बत करने व उनकी मदद करने से हाथ खींचे तो ऐसी इबादत को इस्लाम ने खारिज किया है। क्योंकि असल में इस्लाम का पैगाम है- अगर अल्लाह की सच्ची इबादत करनी है तो उसके सभी बंदों से प्यार करो और हमेशा सबके मददगार बनो। यह इबादत ही सही इबादत है। यही नहीं, ईद की असल खुशी भी इसी में है।



- कोरव-सभा में कृष्ण का समर्थन किया।
- उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं।
- असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था।

सार समाचार

इजराइल ने सुरक्षा गार्ड की हत्या करने वाले फलस्तीनी हमलावरों को गिरफ्तार किया

यरुशलम। इजराइली सेना ने कहा है कि उसने वेस्ट बैक में एक यहूदी बस्ती के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या करने वाले फलस्तीन के दो हमलावरों को गिरफ्तार किया है। वेस्ट बैक में शुक्रवार देर रात किए गए हमले के बाद चलाए तलाश अभियान में ये गिरफ्तारियां की गयीं। इजराइली सैनिकों, विशेष बलों और सीमा पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार बरामद किए। ये हथियार करावत बानी हसन गांव से बरामद किए गए। इस हमले से पहले से जारी इजराइल-फलस्तीन तनाव और बढ़ सकता है। इजराइली सेना ने कहा कि शनिवार तड़के हमलावर एरियल बस्ती के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और सुरक्षा गार्ड को उसकी चौकी पर गोली मार दी और फिर वहां से फरार हो गए। इजराइली प्रधानमंत्री नफताली बेनेट ने सुरक्षा गार्ड के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद एक बयान में उन्होंने कहा, 'कोई भी आतंकवादी हमसे बच नहीं सकता।' इजराइली सेना ने यहूदी बस्ती के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या करने वाले दो फलस्तीनी हमलावरों की तलाश के लिए शनिवार को उत्तरी वेस्ट बैक में एक तलाश अभियान शुरू किया।

पोलियो से हारता पाकिस्तान, एक हफ्ते के भीतर सामने आया दूसरा केस

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में दो साल की एक बच्ची पोलियो से संक्रमित पाई गई है। एक सप्ताह के भीतर पाकिस्तान में पोलियो का यह दूसरा मामला सामने आया है। पोलियो के दो मामले सामने आने के बाद पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारी चिंतित हो गए हैं, क्योंकि देश में आगामी ईद की छुट्टियों के महेनजर बड़े पैमाने पर लोगों के आवागमन में वृद्धि होने के कारण पोलियो के वायरस के फैलने का खतरा भी काफी बढ़ गया है। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान दुनिया के उन दो देशों में शामिल है, जहां पोलियो खत्म होने की स्थिति में है। पोलियो का वायरस बेहद संक्रामक माना जाता है। जब तक पोलियो का सफाया नहीं हो जाता, तब तक दुनिया भर के बच्चों को जीवन भर लकवा होने या वायरस से मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया, आज, एनआईएच, इस्लामाबाद में पाकिस्तान राष्ट्रीय पोलियो प्रयोगशाला ने उत्तरी वजीरिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा जिले की 24 महीने की एक बच्ची के मल के नमूने से टाइप-1 जंगली पोलियो वायरस का पता लगाने की पुष्टि की है। 14 अप्रैल 2022 को बच्ची को लकवा मारने की शुरुआत हुई थी। इससे पहले 22 अप्रैल को 15 महीने के एक बच्चे को पोलियो वायरस के शिकार होने की पुष्टि हुई थी। दोनों ही बच्चे खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली इलाके के रहने वाले हैं।

दुर्लभ 'ब्लैक मून' ने सूर्य पर लगाया ग्रहण, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका व अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखा नजारा

वॉशिंगटन। सन 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक और खगोलीय घटना हुई। वह यह कि सूर्य पर ग्रहण लगाने वाला यह चांद एक ब्लैक मून था। ये सूर्य ग्रहण आंशिक रहा जो दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक और प्रशांत और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में देखा गया। भारतीय समय के अनुसार 30 अप्रैल और 1 मई की मध्य रात्रि को यह 12.15 बजे शुरू हुआ और करीब चार घंटे तक रहा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद आ जाए। चांद के बीच में आने से सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पूरी तरह नहीं पहुंचती और उसकी परछाई पृथ्वी को घेर लेती है। हालांकि साल का पहला सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण था। यानी चांद का कुछ हिस्सा ही पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आने से रोक पाया। इसके साथ ही आंशिक सूर्य ग्रहण भी देखने वाली जगह पर निर्भर करता है। दक्षिण अमेरिका में सूर्य ग्रहण के दौरान करीब 64 फीसदी हिस्से को चांद ने ढक लिया। खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वाले ज्यादातर लोग इस सूर्य ग्रहण को नहीं देख सके, क्योंकि यह अंटार्कटिका, प्रशांत और अटलांटिक महासागर में हुआ जहां आबादी न के बराबर है। हालांकि दक्षिण अमेरिका के देश चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे का अधिकांश भाग, पश्चिमी पराग्वे, दक्षिण-पश्चिमी बोलोविया, दक्षिणपूर्वी पेरू और दक्षिण-पश्चिमी ब्राजील के कुछ हिस्से में यह दिखा। वहीं, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने इसे लाइव देखा।

साल का पहला सूर्य ग्रहण महीने की दूसरी अमावस्या के साथ हुआ, जिसे ब्लैक मून भी कहा जाता है। एक अमावस्या तब होती है जब चांद को कोई भी रोशनी नहीं मिलती है। महीने में एक ही अमावस्या होती है, लेकिन ब्लैक मून बेहद दुर्लभ होता है जो 36 महीने में एक बार होता है। इसमें चांद पूरी तरह सूर्य की ओर होता है, जिससे हमें देखना नहीं है। अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को है। यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस आंशिक सूर्यग्रहण को यूरोप, पश्चिमी एशिया और पूर्वीतर अफ्रीका के हिस्सों से देखा जा सकेगा। इसके बाद 2023 तक अगला सूर्य ग्रहण नहीं है लेकिन 16 मई को चंद्र ग्रहण है।

पुतिन की सेना कब्जे वाले क्षेत्रों में अनाज जब्त कर रही है, यूक्रेन का रूस पर आरोप

कीव। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में रूसी हमलों के बीच देश के उप कृषि मंत्री तारास विसोत्स्की ने कहा है कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में भारी मात्रा में अनाज जब्त कर रही है, जबकि इसके राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेन्स्की ने कहा है कि युद्धग्रस्त देश ईंधन की कमी का सामना कर रहा है। विसोत्स्की ने शनिवार को यूक्रेनी टेलीविजन को बताया, 'आज, इस बात की पुष्टि हो गई है कि जापॉरिजिया, खेरसान, डोनेत्स्क और लुहान्स्क क्षेत्रों से कुल मिलाकर कई लाख टन अनाज बाहर ले जाया गया है।' यूक्रेन दुनिया के प्रमुख अनाज उत्पादकों में से एक है और रूसी आक्रमण ने निर्यात को कम कर दिया है, जिससे विश्व में अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं और आयात करने वाले देशों में गंभीर अनाज की कमी की चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेन्स्की ने शुक्रवार रात कहा कि यूक्रेन को ईंधन की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रूस ने उसके ईंधन बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है और उसके बंदरगाहों को अवरुद्ध कर दिया है। कीव, दनिप्रो और अन्य शहरों में ईंधन की कमी की सूचना मिली है। ईंधन स्टेशनों पर वाहनों को लाइन में खड़ा देखा जा सकता है और अधिकांश जगहों पर वाहन चालक एक बार में केवल 10 लीटर ईंधन खरीद सकते हैं। जेलेन्स्की ने वादा किया था कि अधिकारी कमी को पूरा करने के लिए एक या दो सप्ताह के भीतर ईंधन आपूर्ति ग्वाली खोज लेंगे, लेकिन क्रमबद्ध स्थित रिफाइंडरी पर रूसी मिसाइल हमले के बाद इसे हाकटिन कामकाज कहा। जेलेन्स्की ने कहा, 'तत्काल कोई समाधान नहीं है। इस वृद्धि के साथ, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से मास्को ने यूक्रेन से 10 लाख से अधिक लोगों को निकाला है। लावरोव ने यह बात चीन की एक सरकारी समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में कही। लावरोव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब यूक्रेन ने मास्को पर यूक्रेन के लोगों को जबरदस्ती देश से बाहर भेजने का आरोप लगाया है। लावरोव ने कहा कि इस आंकड़े में 300 से अधिक चीनी नागरिक शामिल हैं।



अमेरिका के स्टोन माउंटन में प्रदर्शकारी मेमोरियल डे पर एकत्र लोगों की ओर जाते हुए।

फिर गृहयुद्ध की ओर बढ़ रही अफगानिस्तान सरकार

अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार के कई धड़ों ने कई प्रांतों में घड़घड़ हमले शुरू किए

काबुल (एजेंसी)

अफगानिस्तान में करीब 2 दशक पहले तालिबान ने साल 2001 में बसंत के महीने में नाटो सेनाओं पर हमले शुरू किए थे। तालिबान की कोशिश थी कि अफगानिस्तान की सत्ता में फिर से काबिज हुआ जाए। अफगान पहाड़ियों पर बर्फ पिघल चुकी थी और तालिबानी आतंकियों ने नाटो सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब जब तालिबान ने सत्ता हासिल कर ली है, एक बार फिर से समय का चक्र घूम गया है। अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार के कई धड़ों ने कई प्रांतों में घड़घड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ये तालिबान विरोधी गुट पश्चिमी देशों की ओर से प्रशिक्षित किए गए उन हजारों अफगान सैनिकों को अपने पाले में ला रहे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में सत्ता में बदलाव के बाद अपनी नौकरी गंवा दी है। इन पूर्व अफगान नेताओं का मानना है कि यह

विद्रोह देश में एक राष्ट्रीय बगावत में बदल जाएगा क्योंकि तालिबानी शासन में महिलाओं, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया जाता है। ये विद्रोही गुट अफगानिस्तान से सटे पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों से मदद हासिल करने की कोशिश में हैं जो तालिबान के आने से चिंतित हैं। वह भी तब जब इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अपने हमले तेज कर दिए हैं।

उधर, तालिबान का मानना है कि यह प्रतिरोध बहुत छोटा है और महत्वहीन है। इस प्रतिरोध से बेहद करीब से जुड़े अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी ने कहा, 'तालिबान के सत्ता में आने के बाद से कुछ भी नहीं बदला है। मुझे पूरा विश्वास है कि तालिबान के खिलाफ हम एक जोरदार बगावत को देखेंगे। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा प्रभावी तालिबानी विरोधी गुट नेशनल रजिस्ट्रेंस फ्रंट है जिसका नेतृत्व अहमद मसूद

कर रहे हैं। अहमद मसूद नार्दन अलावंस के नेता रहे अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह अहमद मसूद के करीबी सहयोगी हैं। ये दोनों ही पंजशीर की घाटी से आते हैं। ये दोनों ही तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद देश से बाहर चले गए थे। उनके समर्थक लगातार पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। वहीं अंदराब इलाके में अफगानिस्तान के पूर्व गृहमंत्री मसूद अंदरई के समर्थक सबसे ज्यादा तालिबान को चोट दे रहे हैं। वे बेहद ऊंचाई पर बसे उत्तरी बगलान इलाके में लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं मजार-ए-शरीफ में भी अफगान वॉरलॉर्ड रहे अल्ला मोहम्मद नूर के समर्थक तालिबान के साथ खूनी संघर्ष में भिड़ गए। इस लड़ाई में नूर का भांजा मारा गया। अफगानिस्तान के कई अन्य प्रांतों में भी हमले तेज हो गए हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने राजनीतिक दलों से मतभेद भुलाने का आह्वान किया



कोलंबो। (एजेंसी)

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने रविवार को कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने मतभेदों को भुला दें और सभी जनहित को ध्यान में रखें। गौरतलब है कि देश इस समय सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है और सरकार से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। राजपक्षे ने अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जनता को दिए संदेश में मतभेद भुलाने और जनहित को ध्यान में रखने की बात कही। इससे एक दिन पहले श्रीलंका की

शक्तिशाली बौद्ध धार्मिक संस्था ने चेतावनी दी थी कि अगर गोटाबाया के बड़े भाई एवं देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश के राजनीतिक और आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए अंतरिम सरकार बनाने के वास्ते इस्तीफा नहीं दिया तो लोग सभी नेताओं को खारिज कर देंगे। गोटाबाया ने ट्वीट किया, हृद्य अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आने का आमंत्रण देता हूँ। आइए राजनीतिक मतभेदों को भूलकर जनहित के संघर्ष में हाथ मिलाएं।

इससे एक दिन पहले श्रीलंका की शक्तिशाली बौद्ध धार्मिक संस्था ने चेतावनी दी थी कि अगर गोटाबाया के बड़े भाई एवं देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश के राजनीतिक और आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए अंतरिम सरकार बनाने के वास्ते इस्तीफा नहीं दिया तो लोग सभी नेताओं को खारिज कर देंगे। गोटाबाया ने ट्वीट किया, हृद्य अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आने का आमंत्रण देता हूँ। आइए राजनीतिक मतभेदों को भूलकर जनहित के संघर्ष में हाथ मिलाएं।

ब्रिटिश कोर्ट ने एडविना-नेहरू के खतों को सार्वजनिक करने से इनकार किया, बेकार गया ब्रिटिश लेखक का प्रयास

लंदन (एजेंसी)

एंड्रयू लोअनी नाम के एक ब्रिटिश लेखक इन दिनों खूब चर्चा में हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना की व्यक्तिगत डायरी प्राप्त करने के लिए लंबी और खचीली कानूनी लड़ाई लड़ी। लेकिन 315 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद वह यह कानूनी लड़ाई हार गए हैं। ब्रिटेन के एक ट्रिब्यूनल ने निजी डायरी और एडविना माउंटबेटन और जवाहर लाल नेहरू के बीच लिखे गए पत्रों को ब्रिटिश लेखक को देने से मना कर दिया है। जज सोफी बकले ने लेखक एंड्रयू लाउनी की अपील को खारिज कर दिया।

एंड्रयू लोअनी उन पत्रों को भी हासिल करना चाहते थे जो एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू ने 1947 और 1960 के बीच एक-दूसरे को भेजे थे। ट्रिब्यूनल ने पाया कि साउथैम्पटन विश्वविद्यालय नेहरू और एडविना के बीच भेजी गई चिट्ठियां नहीं हैं। न्यायाधीश ने पाया कि यूनिवर्सिटी लॉर्ड बेब्रोन की तरफ से कुछ पेपर्स को संभाल कर



रखे हुई थी। यूनिवर्सिटी के पास विकल्प था कि वो इन पत्रों को 100 पाउंड में खरीद सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। न्यायाधिकरण (सूचना अधिकार) के न्यायाधीश सोफी बकले ने लॉर्ड एंड लेडी माउंटबेटन की व्यक्तिगत डायरी और एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत पत्रों को जारी करने के लिए उनकी याचिका को खारिज करने के बाद ब्रिटिश लेखक एंड्रयू लोनी ने कहा कि मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ भी सनसनीखेज बचा है, ये गैर मामूली चीजों के लिए बड़ी कानूनी लड़ाई थी। ब्रिटिश लेखक लोअनी ने इस केस को लड़ने के

लिए 3 लाख पाउंड खर्च किए। उन्होंने पैसों के लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग भी की। उन्होंने कहा कि वे लोग जो कुछ भी छिपाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर चीजें पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। लोअनी ने कहा उन्हें संदेह है कि दस्तावेजों को इसलिए नहीं जारी किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान और भारत के संबंध में हैं। उन्होंने कहा एडविना की प्रकाशित डायरी में जिन्ना के मनोरोगी होने का जिक्र है। हालांकि, मुझे नहीं लगता कि इसका खुलासा होने से पाकिस्तान के साथ संबंध प्रभावित होने वाले हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्स्की ने रूसी सैनिकों से युद्ध न करने का आग्रह किया

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेन्स्की ने शनिवार देर रात रूसी में दिए अपने वीडियो संबोधन में रूसी सैनिकों से यूक्रेन में युद्ध न लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रूस के सैन्य अधिकारी भी जानते थे कि यूक्रेन युद्ध में हजारों रूसी सैनिक मारे जा सकते हैं। जेलेन्स्की ने कहा कि रूस युद्ध के शुरूआती हफ्तों में नष्ट होने वाली अपनी सैन्य टुकड़ियों में नए जवानों की भर्ती कर रहा है, जिन्हें 'जंग लड़ने का अनुभव और प्रेरणा बेहद कम है', ताकि इन टुकड़ियों को युद्ध में दोबारा उतारा जा सके। उन्होंने कहा कि रूस के कमांडर पूरी तरह से समझते हैं कि आने वाले सप्ताह में हजारों सैनिक मारे जाएंगे और हजारों अन्य घायल होंगे। जेलेन्स्की ने कहा, 'रूसी कमांडर अपने सैनिकों से झूठ बोल रहे हैं कि युद्ध लड़ने से इनकार करने पर उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। वे उन्हें नहीं बता रहे हैं कि रूसी सेना शवों के भंडारण के लिए अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर ट्रक की व्यवस्था कर रही है। वे उन्हें रूसी सैन्य अधिकारियों द्वारा भविष्य में होने वाले नुकसान को लेकर किए गए आकलन के बारे में नहीं बता रहे हैं।' यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, 'हर रूसी सैनिक अभी भी अपनी जान बचा सकता है। आपके लिए हमारी भूमि पर आकर अपनी जान कुर्बान करने से बेहतर है कि आप रूस में रहकर जीवित रहें।



पाकिस्तान की नयी सरकार के खिलाफ हुई सऊदी अरब में नारेबाजी, इमरान खान सहित 150 पर केस दर्ज

लाहौर। (एजेंसी)

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने सऊदी अरब में मस्जिद-ए-नवाबी पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके शिष्टमंडल के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और 150 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों में इमरान का मित्रमंडल का हिस्सा रह चुके कुछ सदस्य भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो में देखा जा सकता है कि शरीफ और उनका शिष्टमंडल पिछले बृहस्पतिवार को जैसे ही मदीना में पैगंबर की मस्जिद पर पहुंचा, वैसे ही कुछ जायरीन ह्वाचरह और 'गद्दार' कहकर उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

इन जायरीनों को इमरान का पर यह प्रार्थमिकी दर्ज की गई है। समर्थक माना जा रहा है।

पाकिस्तानी जायरीनों ने शिष्टमंडल के सदस्यों के खिलाफ अपशब्दों का भी प्रयोग किया। मदीना पुलिस ने दावा किया है कि इस संबंध में पांच पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने शनिवार रात इमरान और 150 अन्य लोगों के खिलाफ एक प्रार्थमिकी दर्ज की। उन्होंने बताया कि प्रार्थमिकी में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी और शेख रशीद, इमरान के पूर्व सलाहकार शाहबाज गुल, नेशनल असंबली के पूर्व उपाध्यक्ष कासिम सूरी व लंदन में इमरान के करीबी सहयोगी अनिल मुसरत तथा साहिबजादा जहांगीर भी नामजद हैं। अधिकारियों के अनुसार, लाहौर से लगभग 180 किलोमीटर दूर फैसलाबाद के एक पुलिस थाने में स्थानीय निवासी नईम भाटी की शिकायत पर यह प्रार्थमिकी दर्ज की गई है।

ताइवान पर चीन से युद्ध का बढ़ा खतरा, अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ बनाई जंगी रणनीति

- चीन ताइवान के पास लगातार बड़ी संख्या में भेज रहा है फाइटर जेट और बॉम्बर

वॉशिंगटन (एजेंसी)

यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने ताइवान को लेकर चीन के साथ जंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए पहली बार यूरोपीय सहयोगियों के साथ रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। चीन के बेहद आक्रामक रूख को देखते हुए अमेरिका ने ब्रिटेन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक का मकसद चीन के साथ युद्ध के खतरे को कम करने के लिए ज्यादा करीबी सहयोग की संभावना तलाश करना और संघर्ष की स्थिति के लिए आपात योजना बनाना था। एक

ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय वाइट हाउस के हिंद- प्रशांत क्षेत्र के समन्वयक कुर्त कैम्बेल और चीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की शीर्ष अधिकारी लौरा रोजेनबर्ग ने मार्च में ताइवान को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अहम बैठक की थी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय संघ के सहयोगियों जैसे ब्रिटेन के साथ सहयोग को बढ़ाया जाए। अमेरिका ने यह बैठक ऐसे समय पर की है जब चीन का ताइवान के प्रति आक्रामक रवैया बढ़ता जा रहा है। चीन

ने ताइवान के पास लगातार बड़ी संख्या में फाइटर जेट और बॉम्बर भेज रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ गहन बातचीत शुरू कर दी है। अमेरिका के लौरा रोजेनबर्ग ने मार्च में ताइवान को लेकर ब्रिटिश जॉन अक्विलिनो ने कहा है कि यूक्रेन की जंग ने ताइवान को लेकर चीन के खतरे को रेखांकित किया है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि ताइवान को लेकर हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई कि ब्रिटेन किस तरह से ताइवान के साथ मिलकर कूटनीतिक तरीके से एशिया में प्रतिरोध को बढ़ा

सकता है। अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों में हुई इस चर्चा में यह भी बातचीत हुई कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग शुरू होती है तो ब्रिटेन किस तरह की भूमिका को निभा सकता है। यही नहीं अब अमेरिका ने ताइवान को लेकर अपने सहयोगी देशों को खुफिया सूचना भी साझा करना शुरू कर दिया है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि यह बैठक ताइवान को लेकर हुई अब तक की सभी बैठकों में सर्वोच्च स्तर की थी और सबसे महत्वपूर्ण थी। ताइवान मामलों के एक विशेषज्ञ ने कहा

कि यह एक सही रणनीति है कि ताइवान को लेकर विचार विमर्श बढ़ाया जाए। अमेरिका और ब्रिटेन को युद्ध को लेकर अपने मतभेदों को खत्म करना होगा और संभावित संघर्ष के लिए खुद को तैयार करना होगा। खासतौर पर यूक्रेन जंग को देखते हुए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी हो गया है कि जब भी आवश्यकता हो जोरदार तरीके से जवाब दिया जाए। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच बढ़ते सहयोग का उदाहरण यह है कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 6 महीने तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात था।



सार समाचार

बुलडोजर का डर, 78 हिस्ट्रीशीटों का थाने में सरेंडर, 1500 से ज्यादा अपराधियों ने अपराध न करने की ली शपथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। हरदोई के पिहानी थाने में 78 हिस्ट्रीशीटों ने थाने पहुंच कर सरेंडर किया। बदमाशों के बुलडोजर का खौफ है। इसी खौफ के कारण गले में तख्ती डालकर खुद थाने पहुंचे और अपने गुनाहों का पश्चाताप करने लगे। मिर्जापुर पुलिस का कहना है कि बुलडोजर का खौफ अपराधियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं हरदोई में अब तक करीब 1500 से ज्यादा हिस्ट्रीशीट्स ने थाने पहुंचकर अपराध न करने का किया दावा। यूपी पुलिस का कहना है कि अपराध करके जो प्राप्ती जमा की है। जिन्हें जब करने या गिराने का जो आदेश होता है। उसके परिदृश्य में चिन्हात्रण किया जा रहा है। कुछ संपत्तियां हमने चिन्हित भी की है। इसका निश्चित पर एक हनक अपराधियों पर है। इसके परिणाम स्वरूप ये उसी क्रम में सामने आया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जनपद में 2000 से ज्यादा की संख्या में हिस्ट्रीशीट हैं। जिनके द्वारा विभिन्न अपराध किए गए हैं। उन पर सख्त नजर रखी जाती है। थाने पर हाजिरी के लिए बुलाया जाता है। ऐसा ही बीते दिनों शाहजहापुर में देखने को मिला। पुलिस द्वारा जिले में लगातार मादक पदार्थों और अवैध शराब के विरुद्ध की जा रही लाइवटैक कार्रवाई से डरकर पांच शराब माफिया थाने पहुंच गए। इस दौरान उनके हाथों में तख्ती थी जिस पर लिखा था कि हम लोग शराब बनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर शराब बनाना छोड़ रहे हैं। हम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने आये हैं।

प. बंगाल में आंधी के साथ तेज बारिश ने बरपाया कहर, अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आंधी और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। शनिवार शाम कोलकाता सहित बंगाल के दक्षिणी जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पूर्व मैदानीय जिले के नदीग्राम में बिजली गिरने से 1 महिला और उसके बेटे की मौत हो गई है। खडगपुर में बांस का गेट गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। आंधी-तूफान के चलते कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति को काल बैसाखी कहते हैं। बांग्लादेश में भी भीषण तूफान को काल बैसाखी कहते हैं। नदियां जिले में आंधी के कारण पेड़ की डाल टूटकर गिरने से रवींद्रनाथ प्रमाणिक (62) नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति आंधी की चपेट में आकर घायल हो गया। दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूरघाट में तेज आंधी तूफान की वजह से कई गांवों में भारी नुकसान पहुंचा है। इधर, पूर्व बर्धमान जिले के कटवा-अजीमगंज शाखा में रेल पटरों के उपर ओवरहेड तार पर पेड़ की टकनी गिरने की वजह से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। हालांकि राजधानी कोलकाता में वैसी बारिश नहीं हुई है। कोलकाता व इसके आसपास के जिलों हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना व हुगली में हल्की बारिश हुई है। विभिन्न जिलों में शनिवार को आसमान में काले बादल छाए रहे। पुरुलिया, बाकुडा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, दुर्गापुर व बर्धमान जिले में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में छिटपुट बारिश जारी रहेगी और भीषण गर्मी में थोड़ी कमी आएगी। राज्य में फिर से चक्रवात आने की संभावना है। मौसम विभाग ने मई के पहले सप्ताह में चक्रवात के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इस समय दक्षिण बंगाल में दक्षिण-पश्चिमी हवा चल रही है, जो उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक गंभीर क्षेत्र में एक निम्न दबाव बना रही है। इसके प्रभाव से राज्य में अगले 4 से 5 दिनों तक हल्की और तेज बारिश की संभावना है। कोलकाता व आसपास के जिलों में भी बारिश की संभावना है।

मंदिर तोड़ा जाना हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास : प्रवीण तोगड़िया

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने रविवार को कहा कि मंदिरों का तोड़ा जाना हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास है। तोगड़िया ने राजस्थान के अलवर जिले में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मंदिर तोड़े जाने की घटना के संदर्भ में उक्त बात कही। स्थानीय लोगों का दावा है मंदिर 300 साल पुराना था और उसे गिराए जाने के दौरान गर्भगृह में स्थापित देव मूर्तियों का निरादर किया गया। तोगड़िया ने कहा, 'यह दुखद है... मंदिर नहीं टूटने चाहिए। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक मत हैं कि देश में जहां भी उनकी सरकार है वहां मंदिर नहीं टूटेंगे क्योंकि मंदिर टूटने हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास है।' गौरतलब है कि अलवर के राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 14 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान एक प्राचीन मंदिर को ढहाने को लेकर विवाद हो गया था। इसे लेकर कांग्रेस-भाजपा के बीच आलोच-प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। देश के धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे लाइडस्पीकर हटाने और वैध रूप से लगे लाइडस्पीकर की आवाज धीमी या सीमा के भीतर रखने को लेकर चलाए गए अभियान पर तोगड़िया ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों-निर्देशों का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सभी मस्जिदों से लाइडस्पीकर उतारे जाने चाहिए और यदि मस्जिद में लाइडस्पीकर रखना है तो उसकी आवाज परिसर से बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए।

यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद एक्टर विजय बाबू ने लगाई अग्रिम बेल की अर्जी, एक और महिला ने लगाया जबरन किस करने का आरोप

हैदराबाद। साउथ एक्टर विजय बाबू पर खतरा गहराता जा रहा है। उन पर एक मुसीबत खत्म नहीं हो पा रही है कि दूसरी मुसीबत में वो फंसे दिख रहे हैं। अब उन पर दूसरी महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस महिला का आरोप है कि उन्होंने 20 मिनट की मुलाकात के बाद ही किस करने का प्रयास किया। इससे पहले एक एक्ट्रेस ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद से पुलिस उनकी लाश कर रही है। लुकअउट नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है, इसी बीच उन पर नया आरोप लगाया गया है। उन पर एक महिला ने जबरन किस करने का आरोप लगाया है। महिला ने प्रोड्यूसर और एक्टर विजय बाबू पर इंस्टाग्राम पेज मी टू केरल पर यह आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि विजय ने महज 20 मिनट की मुलाकात में ही उसे किस करने की कोशिश की। महिला ने बताया कि वह काम पाने के लिए एक्टर से मुलाकात के लिए गई थी। उन्हें मिले केवल 20-30 मिनट ही हुए होंगे और एक्टर ने उन्हें किस करने की कोशिश की। पीछता ने कहा कि इस घटना के बाद वह बेहद डर गईं और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से ही दूरी बना ली। महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा जिस समय मैं वहां पहुंची वह शराब पी रहा था। उसने मुझे भी शराब आकर की। मैंने मना कर दिया। इसी दौरान वह बिना किसी रजामंदी के अचानक लिफ्ट पर किस करने के लिए झुका, मैंने दूरी बनाते हुए पीछ हटकर किसी तरह से अपना बचाव करने का प्रयास किया।

पद संभालते ही चीन को लेकर नए सेना प्रमुख का सख्त अंदाज, कहा- एलएसी पर किसी की भी टेढ़ी नजर को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त



मुंबई (एजेंसी)

जनरल मनोज पांडे ने नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वे 29वें सेना प्रमुख बने। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जनरल मनोज पांडेय ने पद संभालते ही चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में नए भारतीय सेना प्रमुख ने कहा कि एलएसी पर अभी स्थिति सामान्य है। यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के लिए हमारे विरोधी द्वारा एकतरफा और उकसाने वाली कार्रवाई की गई जिसका मुझे लगता है कि पर्याप्त जवाब दिया गया है। सेनाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालते हुए आर्मी चीफ पांडे ने कहा कि मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मुझे थल सेना के नेतृत्व का दायित्व

सौंपा जा रहा है जिसे मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के कार्य में बखूबी काम किया है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा कि दिल्ली उसी प्रकार थलसेना का देश निर्माण में उतना ही योगदान रहा है। मैं देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मेरी कोशिश रहेगी कि पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए अच्छे काम को मैं आगे बढ़ाऊँ। इसके साथ ही चीन को लेकर उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच बातचीत की प्रक्रिया जारी है और हम जब दूसरे पक्ष से बात करेंगे तो हमें हल मिलेगा। हमें

विश्वास है कि दूसरे पक्ष से बात करते हुए हमें चल रहे मुद्दों का समाधान मिलेगा। सेना प्रमुख जनरल पांडे ने कहा कि पिछले दो वर्षों में हमने खतरे का आकलन किया है और अपने बलों को फिर से संगठित और पुनर्गठित किया है। उन्होंने कहा, 'जहां तक ??एलएसी की स्थिति का सवाल है, हमारे सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत दृढ़ और संकल्प के साथ मौजूद हैं, यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। नए सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना के जवान महत्वपूर्ण फिजिकल पोজिशन पर तैनात हैं और इस सब में हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम यथास्थिति में किसी भी बदलाव और क्षेत्र के किसी भी नुकसान की अनुमति नहीं देंगे।

सीएम योगी ने त्योहारों पर बिजली आपूर्ति सुचारू रखने दिए निर्देश, नहीं होगी कटौती

लखनऊ (एजेंसी)

भीषण गर्मी के बीच ईद और परशुराम जयंती के त्योहार पड़ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बिजली किल्लत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम-09 के साथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में बिजली की मांग तथा आपूर्ति में भी समन्वय बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के अवसर पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुचारू रखें। कहीं पर भी अनावश्यक कटौती न हो। इसके साथ ही उनका निर्देश है कि सभी धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता, पेयजल आदि के प्रबंध किए जाएं। लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों कोदिल्ली यात्रा के दौरान मेरी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री के साथ बिजली आपूर्ति के संबंध में सकारात्मक बातचीत हुई। तीनों माननीय मंत्रियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। कोयले की



दुलाई के लिए रेलवे हमें अतिरिक्त रैक देने जा जा रहा है तो भारत सरकार से अतिरिक्त बिजली भी प्राप्त होगी। इस दौरान भी रोस्टर के अनुरूप निर्वाह बिजली आपूर्ति के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। फिलहाल स्थिति सामान्य है और रोस्टर के अनुरूप बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल न मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। इस दौरान भी ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया

जाना उपभोक्ता को परेशान तो करता ही है, व्यवस्था के प्रति निराश भी करती है और वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता। ऐसे में समय से बिल और सही बिल दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए टोस कार्ययोजना बनाने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि बिजली आपूर्ति होती रहे इसके लिए बिल का भुगतान जरूरी है। बिजली का उपयोग करने वाले हर उपभोक्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह समय से बिजली बिल का भुगतान करे।

महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि



मुंबई (एजेंसी)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर संयुक्त (एकीकृत) महाराष्ट्र आंदोलन के 105 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आंदोलन के बाद वर्ष 1960 में आज के ही दिन महाराष्ट्र का गठन हुआ था। दिवस कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के बीच मनाया गया था। हालांकि, राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या में निरावट के कारण अब प्रतिबंध एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक (शहीद स्मारक) जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने बाद में एक टवीट में कहा, महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र स्थापना महाराष्ट्र का गठन हुआ था। दिवस कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के बीच मनाया गया था। हालांकि, राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या में निरावट के कारण अब प्रतिबंध एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पत्नी रश्मि ठाकरे

भरूच की रैली में बोले केजरीवाल, दिल से दिला का रिश्ता बनाने गुजरात आया, 'आप' को एक मौका दीजिए

भरूच (गुजरात) (एजेंसी)

अरविंद केजरीवाल मिशन गुजरात पर है और लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर इमानदार सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में हिस्सा लिया। जिसके बाद आप के संयोजक ने जनसभा को संबोधित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि

डालने वाले हैं। मानना पड़ेगा, भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केजरीवाल ने कहा कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। इन्होंने स्कूलों का बुरा हाल कर दिया। बीजेपी को 5 साल और दे दोगे तो भी ये कुछ नहीं करेंगे। हमें एक मौका दे दो। अगर 5 साल में गुजरात के सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं किया तो हमें वोट मत देना। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन दिल्ली की तरह गुजरात भी बदल सकता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में में जज, अफसर और रिश्तेवाले के बच्चे एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं। बीजेपी वाले क्लाट्स पर चला रहे हैं इकेजरीवाल के सरकारी स्कूल खराब हैं। हमें



गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ, आइए, हमारे स्कूल और अस्पताल देखिए। ऐसे ही मत आलोचना करिए। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस तो अब खत्म है, है कि नहीं है। कांग्रेस के अच्छे नेताओं से कहना चाहता हूँ आ जाओ। देश के 2 सबसे अमीर आदमी गुजरात से आते हैं। देश के सबसे गरीब आदिवासी भी गुजरात से ही आते हैं। कांग्रेस और बीजेपी अमीरों के साथ खड़ी है। अमीरों को और अमीर बना रही है। आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है।

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ, आइए, हमारे स्कूल और अस्पताल देखिए। ऐसे ही मत आलोचना करिए। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस तो अब खत्म है, है कि नहीं है। कांग्रेस के अच्छे नेताओं से कहना चाहता हूँ आ जाओ। देश के 2 सबसे अमीर आदमी गुजरात से आते हैं। देश के सबसे गरीब आदिवासी भी गुजरात से ही आते हैं। कांग्रेस और बीजेपी अमीरों के साथ खड़ी है। अमीरों को और अमीर बना रही है। आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है।

गांवों के शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए नीति की जरूरत: शरद पवार

पुणे। (एजेंसी)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने रविवार को गांवों के शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए एक नीति की जरूरत पर जोर दिया। पवार महाराष्ट्र में पुणे जिला परिषद के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने स्थानीय निकायों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। राज्य के 81 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जन्म के पांच दिन बाद ही वह एक स्थानीय निकाय की बैठक में गए थे, क्योंकि उनकी मां स्थानीय निकाय की सदस्य थीं जो उन्हें अपने साथ वहां लेकर गई थीं। पवार ने कहा, 'गांवों के शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए एक नीति की जरूरत है।



शहरीकरण से स्थानीय प्रशासनों पर दबाव बढ़ रहा है जो कोष से संबंधित मुद्दों का भी सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र को इस पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि स्थानीय निकायों की जरूरतें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले पानी की सीमित जरूरत थी, लेकिन अब स्थानीय निकाय हर घर में पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। बिजली की मांग भी बढ़ रही है और महाराष्ट्र में इस सेक्टर पर संकट मंडरा

रहा है। उन्होंने कहा, 'इस पर जब हमारी बैठक हुई, तो कुछ अधिकारियों ने हमें बताया कि ग्राम पंचायतें बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रही हैं। जब मैंने जांच की, तो मैंने इसे सही पाया।' पवार ने गांवों में सीबीएसई स्कूलों को लेकर लोगों की मांग पर भी प्रकाश डाला। पवार ने कहा कि उन्हें हाल में पता चला है कि राज्य के 28 पूर्व जिला परिषद सदस्य विधायक बने, पांच मंत्री बने और एक सांसद भी बना। पवार ने कहा, 'मैंने कभी भी जिला परिषद में काम नहीं किया और न ही कभी उसका चुनाव लड़ा, लेकिन स्थानीय निकाय की एक बैठक में गया। मेरी मां 1938 में एक स्थानीय निकाय के लिए चुनी गईं और वह 1952 तक इसकी सदस्य रहीं। मेरा जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ था और मेरे जन्म के पांच दिन बाद मेरी मां मुझे स्थानीय निकाय की बैठक में ले गईं।

रूटे आजम खान को मनाने अखिलेश की कवायद, मुलाकात के लिए भेजेंगे एक और दूत

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव से रूटे चल रहे मुस्लिम नेता आजम खान से पिछले दिनों शिवपाल सिंह यादव समेत कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से भेजे नेताओं से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। अब सपा गठबंधन के एक और साथी ओम प्रकाश राजभर भी आजम खान से मिलने के लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि वह अखिलेश यादव का संदेश लेकर आजम खान के पास जा सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी आजम खान से मुलाकात की थी। सुहेतदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख आशी राजभर ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि वह आजम खान से मिलना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने उनके वकील से समय निश्चित करने को कहा है। हालांकि, यह पूछे जाने पर कि क्या वह अखिलेश यादव के कहने पर आजम खान से मिलने के लिए जा रहे हैं, राजभर ने इससे इनकार किया और कहा कि वह अपनी इच्छा के मुताबिक ऐसा करने जा रहे हैं। राजभर ने ओपेसी और आजम के बीच तुलना करते हुए यह भी कहा कि आजम का यूपी में शिक्षा चलता है और ओपेसी की यहां कोई पकड़ नहीं है। राजभर ने शिवपाल और आजम खान की मुलाकात के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया और कहा कि भाजपा के कहने पर ही ऐसा हुआ है। राजभर ने कहा, 'शुरुआत हुआ इस बात से कि शिवपाल जी भाजपा में जा रहे हैं।

द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को दर्शाते वाली पुस्तिका हृदयिल्ली विश्वविद्यालय: एक झलक भी जारी की गयी। शिक्षा मंत्री धर्मंद प्रधान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने से छात्रों की रचनात्मकता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय के महत्व पर जोर दिया गया है। स्थानीय छात्रों की रचनात्मकता को दिशा देने में मदद करती है। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने कहा, हमने अकादमिक उत्कृष्टता के 100 साल पूरे कर लिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कर रहा है। हम भारतीयों के जीवन में अपना योगदान देना जारी रखेंगे।



उपराष्ट्रपति वैकैया नायडू का बयान, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए

नयी दिल्ली। (एजेंसी)

उपराष्ट्रपति एम वैकैया नायडू ने मातृ में शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए रविवार को कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृ में होनी चाहिए। नायडू ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शताब्दी समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को हमारी संस्कृति पर भी ध्यान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा, यदि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृ में दी जाए तो वे उसे आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन, यदि प्रारंभिक शिक्षा किसी अन्य में दी जाती है, तो पढ़ने उन्हें वह सीखनी होगी और फिर वे समझेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को

के उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। उन्होंने कहा, कल प्रधानमंत्री मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं की होना चाहिए। केवल अदालतों ही क्यों, इसे हर जगह लागू किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 साल पूरे करने पर बधाई भी दी। नायडू ने कहा, मैं इस विश्वविद्यालय की उन्नति, विकास और प्रगति के लिए तथा इसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक बनाने के लिए सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। नायडू ने इस अवसर पर स्नातक पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2022 (हिंदी संस्करण) और स्नातक पाठ्यचर्या की रूपरेखा- 2022 (संस्कृत संस्करण) भी जारी किया। इसके अलावा विश्वविद्यालय

हमारे स्कूलों को बुरा हाल कर दिया। बीजेपी को 5 साल और दे दोगे तो भी ये कुछ नहीं करेंगे। हमें एक मौका दे दो। अगर 5 साल में गुजरात के सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं किया तो हमें वोट मत देना। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन दिल्ली की तरह गुजरात भी बदल सकता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में में जज, अफसर और रिश्तेवाले के बच्चे एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं। बीजेपी वाले क्लाट्स पर चला रहे हैं इकेजरीवाल के सरकारी स्कूल खराब हैं। हमें

प्राइवेट संस्थाओं और निजी विश्वविद्यालय को लेकर आयोजित हुआ 97 वां आरटीआई वेबिनार

प्राइवेट यूनिवर्सिटी से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं की जानकारी आरटीआई के दायरे में - सूचना आयुक्तराहुल सिंह।

सूचना छिपाने और प्राप्त करने का संघर्ष सदियों पुराना है - राजेन्द्र गहरवार

क्रांति समय, सुरत

www.krantisamay.com

www.epaper.krantisamay.com

www.rti.krantisamay.com

सूचना के अधिकार कानून और प्राइवेट संस्थान जैसे स्कूल, नर्सिंग होम, निजी विश्वविद्यालय, सहकारी

संस्थाएं आदि से जानकारी कैसे प्राप्त करें इन विषयों को लेकर 97 वां राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के

तौर पर पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप, वर्तमान मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त राहुल सिंह, माहिती अधिकार मंच मुंबई

के संयोजक भास्कर प्रभु एवं राजेंद्र सिंह गहरवार सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, और उनकी टीम के द्वारा किया गया।

शासन द्वारा आंशिक वित्त पोषित संस्थाएं भी आरटीआई के दायरे में - पूर्व सूचना आयुक्त आत्मदीप

कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त आत्मदीप ने लगभग 20 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया जिसमें उन्होंने बताया कि आज के दौर में कई ऐसी संस्थाएं जो सहकारिता विभाग से संबंधित हैं अथवा प्राइवेट किस्म के संस्थान हैं वह ज्यादातर आरटीआई के दायरे में आते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि जब से शिक्षा के अधिकार का सरकार ने प्राइवेट स्कूलों, सीटें रिजर्व करने के निर्देश स्कूलों में शासन की अंतः स्वाभाविक तौर पर के दायरे में आ जाते हैं अपने कार्यकाल के दौरान दुकानों को लेकर उन्होंने जिसके बाद मध्य प्रदेश के सभी राशन की दुकानें आरटीआई के दायरे में आ चुकी हैं और इसके लिए विधिवत दिशानिर्देश भी जारी हो चुके हैं।



इसी प्रकार अन्य निजी संस्थानों के विषय में उनके द्वारा बताया गया कि यदि निजी संस्थानों के विषय में जानकारी चाहिए तो उसके लिए उस जिम्मेदार विभाग से बहुत सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है जहां संबंधित निजी संस्थान अपनी जानकारीयां समय-समय पर देते रहते हैं।

विश्वविद्यालय नियामक आयोग के विषय में भी उन्होंने बताया कि यहां भी निजी विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारीयां भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

ट्रस्ट और सहकारी संस्थानों भी आरटीआई के दायरे में - सूचना आयुक्तराहुल सिंह

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्तराहुल सिंह ने पार्टिसिपेंट्स के प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि ट्रस्ट और सहकारी संस्थाएं भी आरटीआई के दायरे में आती हैं। उन्होंने इसी संदर्भ में एक आरटीआई के विषय में चर्चा की और कहा कि उसकी जानकारी के लिए उन्होंने आदेशित किया था। ट्रस्ट के सवाल पर अभी हाल ही में शारदा देवी मंदिर ट्रस्ट के विषय में जाने पर प्रशासक को 25 हजार का नोटिस भेजा गया था। अपने आदेश का उन्होंने आंशिक तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से जिसमें शासन अंतर्गत रहता है के दायरे में आते हैं हालांकि जानकारी न देने से बचने के विभिन्न तरीके उनके द्वारा अपनाए जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं।



उन्होंने मत्स्य संघ सहकारी संस्था को आरटीआई के दायरे में लाने संबंधी मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश अरविंद्र कुमार शुक्ला के आदेश का भी हवाला दिया। इसी प्रकार दर्जनों प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने प्रतिभागियों के समाधान किए।

यदि आरटीआई कानून को मजबूत करना है तो सबको आगे आकर आवाज उठानी पड़ेगी

कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक्जैम्पसन को लेकर आरटीआई कानून को कमजोर किया जा रहा है। गिरीश रामचंद्र देशपांडे और अन्य जो भी निर्णय दिए गए हैं वह तर्कसंगत नहीं हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बहुतायत में जानकारीयां मात इसी कारण नहीं दी जा रही है जिससे आरटीआई कानून कमजोर होता जा रहा है। भास्कर प्रभु

ने भी विस्तार से अपने विचार रखे और कहा कि जो सूचना आयुक्त कार्य नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध मोर्चा खोला जाना चाहिए और न केवल जनता को बल्कि अच्छे कार्य करने वाले सूचना आयुक्तों को भी इसके विरुद्ध बात करनी चाहिए। आज ब्यूरोक्रेट्स क्षेत्र से आने वाले सूचना आयुक्त आयोगों में बैठकर मात जानकारीयां दबा रहे हैं जो काफी चिंता का विषय है और इससे दिन प्रतिदिन आरटीआई कानून कमजोर होता जा रहा है।



कार्यक्रम में देश के विभिन्न कोनों से आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता,

ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सामाजिक चिंतक जुड़े जिन्होंने अपने अपने प्रश्न रखे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया।

गोरखपुर से प्रदीप सिंह ने भी ग्राम पंचायत और मनरेगा से संबंधित जानकारी को लेकर उनके द्वारा लगाई गई आरटीआई पर जब जवाब नहीं मिला तो उसके विषय में चर्चा की जिस पर सूचना आयुक्तों ने बताया कि हमेशा ही आवेदक

को बिंदुवार जानकारी मांगनी चाहिए एवं जानकारी बृहद किस्म की नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोक सूचना अधिकारी मात जानकारी न देने का बहाना बनाते हैं इसलिए आवेदकों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है।

सूचना छिपाने और प्राप्त करने का संघर्ष सदियों पुराना है - राजेन्द्र गहरवार

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े पत्रिका सतना सागर संभाग के संपादक राजेंद्र सिंह गहरवार ने विस्तृत चर्चा की और चर्चा करते हुए सूचना प्राप्त करने संबंधी कई अनुभव साझा किए। उनके द्वारा बताया गया कि जब आरटीआई कानून अस्तित्व में नहीं था तब भी सूचना प्राप्त करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी और कहीं अगल बगल से जानकारीयां प्राप्त कर पेपर पत्रिकाओं में छापना पड़ता था। आरटीआई कानून आने के बाद यह सब काफी आसान हुआ है फिर भी जब लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा जानकारीयां समय पर नहीं दी जाती तो पेपर पत्रिकाएं महीनों तक इंतजार नहीं कर सकते इसलिए कहीं न कहीं से जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। अतः देखा जाए तो पेपर पत्रिकाओं में छपने छपाने से संबंधित सूचनाएं आज भी 75 प्रतिशत से अधिक बिना आरटीआई के माध्यम से ही

प्राप्त की जा रही हैं। राजेंद्र गहरवार ने बताया कि सूचना प्राप्त करने और छिपाने का यह जो सिलसिला है सदियों पुराना है। अखबार और पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों के लिए हमेशा ही सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं जबकि गड़बड़ करने वाले और भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के लिए सूचनाएं समाज तक न जा पाए इसका हमेशा ही भरसक प्रयास करते हैं। राजेंद्र गहरवार ने एक खुलासा किया और बताया कि सरकार बिजली के उपयोग के लिए 10 हजार करोड़ का पेमेंट बिजली कंपनियों को कर चुकी है लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी हम आवश्यक बिजली के लिए परेशान हो रहे हैं।

मैहर शारदा मंदिर ट्रस्ट के विषय में उन्होंने बताया कि इसके पहले नित्यानंद मिश्रा अधिवक्ता जबलपुर के द्वारा जानकारीयां चाही गई थी जिस के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया

गया था लेकिन आश्चर्य है कि एक बार पुनः जब आवेदक आनंद श्रीवास्तव के द्वारा आरटीआई दायर की गई और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो प्रशासक और एसडीएम मैहर द्वारा जानकारी छुपाने का

विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता

श्री राहुल सिंह जी
सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश

श्री अजय उप्रेती जी
सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश

श्री शैलेश गांधी जी
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त

श्री आत्मदीप जी
पूर्व सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश

श्री राजेंद्र गहरवार जी
संपादक पत्रिका सतना - सागर

श्री भास्कर प्रभु जी
RTI कार्यकर्ता एवं विशेषज्ञ

प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि रोपवे से संबंधित जानकारी चाही गई तो जो खुलासा हुआ उसमें पता चला कि रोपवे से आने जाने वाले लोगों का डाटा ही मौजूद नहीं है। इस प्रकार इसमें करोड़ों का घालमेल किया जाता रहा बाद में शिकायत हुई और कार्यवाही प्रचलित है।

ब्लैक मेलिंग जैसे मामलों की चर्चा करते हुए राजेंद्र सिंह गहरवार ने बताया कि न केवल आरटीआई कार्यकर्ता बल्कि पत्रकारों के ऊपर भी समय-समय पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं और देखा जाए तो सच्चाई यह है कि

ब्लैकमेलिंग का प्रतिशत अत्यंत न्यून है जो शून्य दशमलव शून्य शून्य से भी कहीं नीचे है लेकिन उसकी आड़ में विभाग और अधिकारी आरटीआई कानून को कमजोर करना चाह रहे हैं। सरकार यह नहीं देखती कि आरटीआई कानून से कितना अधिक फायदा है। आम जनता अपने अधिकारों का प्रयोग कर पा रही है और सशक्त बन रही है। पत्रकारिता में भी कुछ लोग गलत उपयोग कर बदनाम करते रहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पूरा पत्रकारिता जगत ही गलत है क्योंकि यदि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं होता तो आज समाज का क्या होता स्वतः ही आकलन किया जा सकता है।

राजेंद्र गहरवार ने बस कंडक्टर और पत्रकार एवं अमर सिंह कलेक्टर रीवा के कार्यकाल में भूख से मरने वाले व्यक्ति से संबंधित प्रकाशन पर चर्चा करते हुए कुछ बड़े ही दिलचस्प उदाहरण प्रस्तुत किए।